प्रधानमंत्री आज अयोध्या में

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोक शक्ति

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर आज फहरायेगा धर्म ध्वज

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 325 | रायपुर | मंगलवार 25 नवंबर 2025 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G/RYP DN/71/2023-25

नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र, 89 साल की उम्र में निधन,

मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार

एजेंसी

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है. वह 12 नवंबर को ही अस्पताल से घर लौटे थे. धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. लेकिन 12 नवंबर की सुबह करीब साढ़े सात बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. उसके बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था. उनका सोमवार को मुंबई के विले पार्ले में अंतिम संस्कार कर दिया गया. उनके अंतिम दर्शन करने के लिए अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, शबाना आजमी और अनिल कपूर समेत कई दिग्गज सितारे पहुंचे. श्मशान घाट पर धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल को काफी इमेशनल देखा गया. यही नहीं, करण देओल भी दादा के अंतिम संस्कार से लौटते समय काफ ी इमोशनल दिखे. हेमा मालिनी की भी आंखें नम थीं. धर्मेंद्र और हेमा ने 1980 में शादी की थी और आखिर 45 साल बाद दोनों को साथ छूट गया. धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के साहनेवाल गांव में हुआ था. 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और वह हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड रखते हैं. धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया और 1960 के दशक में पॉपुलर हो गए. उनका आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आए दिन बहार के ने उन्हें इस दशक में रातोंरात पॉपुलैरिटी दिलाई. वहीं उन्हें हीमैन का दर्जा दिया गया, जो आज भी कायम है. उनकी फिल्में शोले से लेकर यमला पगला दीवाना तक सभी फिल्में फैंस की फेवरेट रही हैं. धर्मेंद्र ने शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश और ड्रीम गर्ल जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं।

प्रधानमंत्री 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे

पीआईबी

प्रधानमंत्री शाम लगभग 4 बजे भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित 'पांचजन्य' का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद, वे महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा करेंगे। यह एक गहन अनुभवात्मक केंद्र है जहां महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है जो इसके स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं।

शाम लगभग 4:30 बजे, प्रधानमंत्री सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री पूज्य गुरु के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में, भारत सरकार एक वर्ष तक चलने वाला स्मरणोत्सव मना रही है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए

देश के 53वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत

राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ

नई दिल्ली ,संवाददाता।

जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद वह देश के लिए 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई समेत कई गणमान्य मौजूद रहे।

जस्टिस सूर्यकांत ने सीजेआई भूषण आर गवई की जगह ली है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सीजेआई गवई की सिफारिश के बाद 'संविधान के आर्टिकल 124 के क्लॉज (2) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए' जस्टिस सूर्यकांत को भारत का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी, 1962 को हरियाणा के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उन्होंने 1984 में हिसार से अपनी लॉ यात्रा शुरू की और फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ चले गए। इस दौरान उन्होंने कई तरह के संवैधानिक, सर्विस और सिविल मामलों को संभाला, जिसमें यूनिवर्सिटी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, बैंक और यहां तक कि खुद हाईकोर्ट को भी रिप्रेजेंट किया। जुलाई 2000 में उन्हें हरियाणा का सबसे कम उम्र का एडवोकेट जनरल बनाया गया। इसके बाद, 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया और 9 जनवरी 2004 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का परमानेंट जज बनाया गया। बाद में, उन्होंने अक्टूबर 2018 से 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अपनी पदोन्नति तक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया। नवंबर 2024 से वे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं।

भाई-बहन के पैर छुए, पूर्व CJI गवई से मिले, मोदी-शाह से भी भेंट

CJI पद की शपथ लेने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने भाई और बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल भी मौजूद थे। जस्टिस सूर्यकांत को 30 अक्टूबर 2025 को CJI नियुक्त किया गया था और वो 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे। दरअसल CJI बी आर गवई 65 साल के पूरे हो गए हैं, जिसके चलते अब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में CJI का पद छोड़ने से पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को अगला CJI बनाने की परंपरा जारी रखी और जस्टिस सूर्यकांत को अपना उत्तराधिकारी चुना है।

PNB धोखाधड़ी : मेहुल चोकसी के कुर्क फ्लैटों की नीलामी होगी

एजेंसी

310 करोड़ की संपत्ति लिक्विडेटर को मिलीईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 21 नवंबर को मुंबई के बोरीवली (पूर्व) स्थित तत्व ऊर्जा परियोजना के इन फ्लैटों को परिसमापक को सौंपकर यह कदम उठाया। ईडी ने एक बयान में कहा कि मेहुल चोकसी और अन्य से जुड़े धन शोधन मामले में कुर्क की गई इन संपत्तियों का अब पीड़ितों, सुरक्षित लेनदारों और अन्य पात्र दावेदारों के लाभ के लिए मुद्रीकरण किया जाएगा। भगोड़े मेहुल चोकसी से जुड़े करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में संपत्तियों की वापसी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में चार कुर्क फ्लैटों को परिसमापक को सौंप दिया है। ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 21 नवंबर को मुंबई के बोरीवली (पूर्व) स्थित तत्व ऊर्जा परियोजना के इन फ्लैटों को परिसमापक को सौंपकर यह कदम उठाया। ईडी ने एक बयान में कहा कि मेहुल चोकसी और अन्य से जुड़े धन शोधन मामले में कुर्क की गई इन संपत्तियों का अब पीड़ितों, सुरक्षित लेनदारों और अन्य पात्र दावेदारों के लाभ के लिए मुद्रीकरण किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण को नई दिशा मिलने की उम्मीद

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ अहम मुलाकात

नई दिल्ली, लोकशक्ति

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री चिराग पासवान से उनके कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। जिसमें छत्तीसगढ़ से जुड़े कई जनहित विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राज्य में खाद्य सुरक्षा, कृषि आधारित उद्योग, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री ने मंत्री से अनुरोध किया कि निफ्टेम संस्थान छत्तीसगढ़ में स्थापित की जाए ताकि राज्य के युवाओं को आधुनिक खाद्य तकनीक, उद्यमिता और नए रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण मिल सकें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि की दृष्टि से एक मजबूत राज्य है और यहां ऐसे संस्थान से हजारों छात्रों तथा किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे इस विषय पर हर संभव सहयोग देंगे तथा इसे गंभीरता से विचार में लेंगे।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने यह आग्रह भी किया कि वर्ल्ड फूड इंडिया के रीजनल समिट का आयोजन रायपुर में किया जाए। उन्होंने कहा कि रायपुर की समृद्ध खाद्य परंपरा, बेहतर कनेक्टिविटी और विविधता इसे ऐसे आयोजन के लिए आदर्श स्थान बनाती है। यह फेस्टिवल क्षेत्र की पाक परंपराओं को बढ़ावा देगा और नए खाद्य-आधारित उद्यमों को आगे बढ़ने का अवसर देगा।

राज्य ने आग्रह किया कि यह आयोजन दिल्ली के वर्ल्ड फूड इंडिया या गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट फूड फेस्ट की तर्ज पर हर दो साल में आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में खाने की चीज़ों की जाँच के लिए फूड टेस्टिंग लैब और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए फूड इरेडिएशन यूनिट्स बनानी हैं, जिसके लिए राज्य केंद्र मंत्रालय की मदद चाहता है। उन्होंने कहा कि धान और फल-सब्ज़ी पर आधारित उद्योगों में बड़े निवेशकों को जोड़ने से किसानों, महिलाओं के स्व-सहायता समूहों और गाँवों में रोजगार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में राज्य ने फूड प्रोसेसिंग को खास महत्व दिया है और निवेशकों को कई अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

पश्चिम मध्य रेल ने अक्टूबर माह में कबाड़ से कमाए 52 करोड़, स्क्रैप डिस्पोजल से हुआ ये लाभ

जबलपुर. पश्चिम मध्य रेलवे ने गत अक्टूबर माह में कबाड़ (स्क्रैप) से 52 करोड़ रुपयों से अधिक का राजस्व अर्जित किया है. रेल मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शुरू किए गए एक महीने के विशेष अभियान 5.0 में पश्चिम मध्य रेल ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता, लंबित मामलों का निपटान और प्रभावी अभिलेख प्रबंधन करना था। यह अभियान रेलवे बोर्ड की गहन निगरानी और मार्गदर्शन में सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों में लागू किया गया. इस विशेष अभियान 5.0 में पश्चिम मध्य रेलवे स्क्रैप डिस्पोजल का लक्ष्य पूरा करने में हमेशा ही अग्रणी रहा है। जिसने विशेष अभियान 5.0 के दौरान रूपये 51 करोड़ 70 लाख का स्क्रैप डिस्पोजल किया है।

आरएसएस को विदेशी मदद नहीं मिलती, सिर्फ समाज का सहयोग : योगी

लखनऊ एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोक को भारत का हर सनातन धर्मावलंबी जीवन का मंत्र मानकर आदर भाव के साथ आत्मसात करने का प्रयास करता है। श्रीमद्भगवद्गीता नई प्रेरणा देती दिखाई देती है। श्रीमद्भगवद्गीता धर्म से ही शुरू होती है और अंत में भी उसी मर्म के साथ विराम लेती है। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है। हर व्यक्ति अपने पंथ, संप्रदाय, और उपासना विधि के अनुरूप आस्था को तय कर लेता है, लेकिन मुख्य रूप से धर्म हमारे यहां जीवन जीने की कला है। हमने इसे ही 'वे ऑफ लाइफ' के

रूप में कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित 'दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव' में रविवार को ये बातें कहीं।

सीएम योगी ने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता भगवान की दिव्य वाणी है। उन्होंने श्लोक 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः' को सुनाया। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता होगा, जहां युद्ध का मैदान धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता हो, लेकिन हमने हर कर्तव्य को पवित्र भाव के साथ माना है। अच्छा करेंगे तो पुण्य और गलत करेंगे तो पाप के भागीदार बनेंगे। यह मानकर हर सनातन धर्मावलंबी अच्छा करने का प्रयास करता है। भारत ने विश्व मानवता को प्राचीन काल से ही संदेश दिया है। हमने कभी नहीं कहा है कि जो मैं कह रहा हूं, वही सब कुछ है या हमारी उपासना विधि सर्वश्रेष्ठ है। सब कुछ होते हुए भी हमने कभी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा। जो भी आया, उसे शरण दिया। जिसके ऊपर भी विपत्ति और चुनौती आई, सनातन धर्मावलंबी उसके सहयोग के लिए खड़ा हो गया।

विदेश | आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और अगली पीढ़ी के डेटा केंद्रों जैसी उभरती प्रौद्योगिकी

भारत-कनाडा द्विपक्षीय व्यापार और मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ावा देंगे

पीआईबी

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में इंडो-कैनेडियन बिज़नेस चैंबर को संबोधित करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों, खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और आपूर्ति-श्रृंखला विविधीकरण में कनाडा के साथ सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और अगली पीढ़ी के डेटा केंद्रों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत को दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक एसटीईएम स्नातकों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि कनाडा और भारत सहयोगी हैं और दोनों देश व्यवसायों और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा की साझेदारी आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है और व्यापार, निवेश तथा उभरते क्षेत्रों में निरंतर बढ़ते सहयोग के साथ, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध मज़बूत और स्थिर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कनाडा

के प्रधानमंत्री श्री मार्क कार्नी के बीच जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान हाल ही में हुई बैठक का उल्लेख करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौते (सीईपीए) और वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सीईपीए दोनों देशों के बीच विश्वास को दर्शाता है, निवेशकों के विश्वास को मजबूत करता है और आपसी सम्मान के आधार पर समस्याओं के समाधान के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है।

श्री गोयल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत का 500 गीगावाट का राष्ट्रीय पावर ग्रिड, जिसमें 250 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता शामिल है, एआई-संचालित बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को दोगुना करके 500 गीगावाट करने की भारत की महत्वाकांक्षा, देश को एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में स्थापित करती है, और भारत उन गिने-चुने लोकतंत्रों में से एक है जो वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी दरों पर चौबीसों घंटे वास्तविक स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम हैं। इस महीने की शुरुआत में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री के साथ हुई सातवीं मंत्रिस्तरीय वार्ता का उल्लेख करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने व्यापार संबंधों को पुनर्जीवित करने और द्विपक्षीय व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की संभावनाओं पर सहमति व्यक्त की है।

भारतीय सामानों पर लगेगा जीरो टैरिफ, अफगानिस्तानी मंत्री ने जताई प्रतिबद्धता

एजेंसी

अफ़ग़ानिस्तान के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन ने कहा कि नई दिल्ली और काबुल द्विपक्षीय व्यापार को पुनर्जीवित करने और विस्तारित करने के काफ़ी क़रीब पहुँच गए हैं। दोनों पक्षों ने वीज़ा और कनेक्टिविटी संबंधी उन मुद्दों को सुलझा लिया है जो व्यापारिक संबंधों में बाधा बन रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों देश अब गर्व की भावना के साथ काम कर रहे हैं और उनका लक्ष्य व्यापार को मौजूदा 1 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर से आगे ले जाना है। नूरुद्दीन ने कहा कि वीज़ा और सीधी उड़ानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है, जिससे व्यापारियों और यात्रियों की सुगम आवाजाही का रास्ता साफ़हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि चाबहार लिंक, ज़मीनी मार्गों और हवाई गलियारे पर भी बातचीत आगे बढ़ रही है। मंत्री ने कहा कि दोनों देश व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह को सक्रिय करने पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत प्रत्येक पक्ष एक-दूसरे की राजधानी में एक वाणिज्यिक अटैची तैनात करेगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह एक महीने के भीतर लागू हो जाएगा। व्यापारिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए, भारत और अफ़ग़ानिस्तान एक संयुक्त वाणिज्य मंडल स्थापित करेंगे और व्यापार विस्तार को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ़में पारस्परिक रूप से कमी की जाएगी। उद्योगों को दोनों पक्षों के बाज़ारों तक सीधी पहुँच प्रदान करने के लिए हर साल व्यापार मेलों का आयोजन किया जाएगा। अफ़ग़ान निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अफ़ग़ान खाद्य वस्तुओं पर एफ़एसएसएआई शुल्क शून्य हो जाएगा, जिससे भारत में कृषि और प्रसंस्कृत वस्तुओं का प्रवेश आसान हो जाएगा। भारत इलाज कराने आए अफ़ग़ान नागरिकों के लिए और वीज़ा जारी करेगा। नूरुद्दीन ने बताया कि अफ़ग़ानिस्तान ने एक प्रमुख भारतीय अस्पताल श्रृंखला को देश में शाखा खोलने के लिए आमंत्रित किया है, और भारत इस सहयोग के तहत तकनीशियन और विशेषज्ञ भेजने वाला है। वित्तीय मामलों पर, उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में कुछ छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, लेकिन दोनों देशों के बैंक संपर्क में रहेंगे और सहयोग को आगे बढ़ाएँगे।

नूरुद्दीन ने कहा कि वीज़ा और सीधी उड़ानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है, जिससे व्यापारियों और यात्रियों की सुगम आवाजाही का रास्ता साफ़ हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि चाबहार लिंक, ज़मीनी मार्गों और हवाई गलियारे पर भी बातचीत आगे बढ़ रही है।

पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका क्यों

पाकिस्तान कभी तालिबान को अपना दोस्त और भारत के दुश्मन के तौर पर देखता था। जब अगस्त 2021 में तलिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तब भी पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत के तौर पर देखा। पाकिस्तानी सेना, राजनेता और सामरिक विशेषज्ञों ने इस पर खुशी जताई। लेकिन, बीतते समय के साथ पाकिस्तान और तालिबान के संबंध खराब होते चले गए। वहीं, इसके ठीक उलट भारत के साथ तालिबान के संबंध मजबूत हुए। आज तालिबान लगातार भारत के साथ संपर्क बढ़ा रहा है। वहीं, तालिबान की पाकिस्तान के साथ सीमा पर सैन्य झड़पें हो रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले तालिबानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत का दौरा किया था। उनके दौरे के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से खास तौर पर मंजूरी दिलाई थी।

डोनाल्ड ट्रंप को लगा 1.1 अरब डॉलर का करारा झटका, बिटकॉइन क्रैश से डूबी संपत्ति

वॉशिंगटन एजेंसी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबर सामने आई है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार ट्रंप को अपनी संपत्ति में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। फोर्ब्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की नेटवर्थ में सीधे 1.1 अरब डॉलर की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस वित्तीय झटके के पीछे सबसे बड़ी वजह क्रिप्टोकरेंसी बाजार में मचा कोहराम और विशेष रूप से बिटकॉइन का क्रैश होना बताया जा रहा है, जिसका सीधा असर बाजार की धारणा और उनकी कंपनी के वैल्यूएशन पर पड़ा है। फोर्ब्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति अब घटकर 6.2 अरब डॉलर रह गई है, जो इसी साल सितंबर महीने में 7.3 अरब डॉलर के उंघ स्तर पर थी।

रिपोर्ट बताती है कि यह गिरावट मुख्य रूप से तब आई जब उनकी मीडिया और टेक्नोलॉजी कंपनी 'टीएमटीजी' (TMTG) के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। यह कंपनी शेयर बाजार में डीजेटी टिकर के तहत कारोबार करती है और इसके शेयरों का गिरता ग्राफ ट्रंप की नेटवर्थ के कम होने का बड़ा कारण बना है।

बाजार के जानकारों के मुताबिक, बीते शुक्रवार को बिटकॉइन समेत अन्य प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी में आई भारी गिरावट के बीच ट्रंप की कंपनी का स्टॉक भी संभल नहीं पाया और यह 10.18 डॉलर के स्तर तक लुढ़क गया।

नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय में जनजातीय गौरव दिवस पर गरिमामय व्याख्यान कार्यक्रम संपन्न

एमसीबी, नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक भव्य एवं सारगर्भित व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीतः ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान रहा, जिसके माध्यम से जनजातीय समुदाय की आदिम संस्कृति, स्वाभिमान की परंपरा, राष्ट्रनिर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तथा सामाजिक समरसता पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्य वक्ता ने जनजातीय समाज की गौरवगाथा रखी - कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री परमेश्वर सिंह मरकाम, अध्यक्ष–जनजातीय गौरव समाज, ने अपने प्रभावी संबोधन में कहा कि जनजातीय समुदाय का इतिहास भारत की मूल सांस्कृतिक पहचान का आधार है। उन्होंने बताया कि जनजातीय समाज की जीवन पद्धति प्रकृति-पूजन, समानता, सहयोग और सामुदायिक न्याय व्यवस्था पर आधारित रही है, जो आज के आधुनिक समाज के लिए भी प्रेरणास्त्रोत है। श्री मरकाम ने वीर नारायण सिंह, बिरसा मुंडा, गुंडाधुर ,अहिल्याबाई जैसे जननायकों के संघर्षों को स्मरण करते हुए युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

मुख्य अतिथि ने छात्राओं के विकास की दिशा में चल रही पहलें बताई

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती नीलू जायसवाल, अध्यक्ष–जनभागीदारी समिति, ने कहा कि महाविद्यालय में जनजातीय छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रवृत्ति योजनाएँ, कौशल-विकास गतिविधियाँ तथा सुरक्षा-सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जनजातीय छात्राओं से शैक्षणिक अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने और समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाने की प्रेरणा दी। श्रीमती जायसवाल ने अपने वक्तव्य में कहा कि जनजातीय समाज ने सदैव अपनी परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण किया है। जनजातीय समुदाय ने 'जन-जंगल-जमीन' को सर्वोपरि माना है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आधुनिक समाज के लिए प्रेरणा-स्रोत हैं। साथ ही उपस्थित जनों से आह्वान किया कि वे देश की संस्कृति और विरासत को मजबूती से समर्थन दें।

विशिष्ट वक्ता ने जनजातीय वीरता और परंपराओं का स्मरण कराया

विशिष्ट वक्ता श्री हंसराज सिंह, पूर्व अध्यक्ष–जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़, ने कहा कि जनजातीय इतिहास केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की अद्भुत गाथा है। उन्होंने जंगल आंदोलनों, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोहों तथा जनजातीय नायकों के असाधारण योगदान का उल्लेख किया। श्री सिंह ने बताया कि जनजातीय समाज हमेशा से पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग का जीवंत उदाहरण रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी मातृ शक्ति और पितृ शक्ति, जो समय के साथ कहीं खोती चली गई थीं, आज जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से फिर से सम्मानपूर्वक उजागर हो रही हैं।

लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को देश में मिलाने की अहम भूमिका निभाई – विष्णुदेव साय

0 सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एकता नगर सहित देशभर में हो रहे विविध आयोजन

रायपुर, देश के प्रथम उपप्रधानमंत्री एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर को जन्मोत्सव धुमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में विविध आयोजन हो रहे हैं। सरदार पटेल ने आजादी के समय 562 रियासतों के विलिनीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। अखंड भारत को पूर्ण स्वरूप देने की सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिश ने भारत को एक नई दिशा दी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता नगर में युनिटी फॉर स्टेच्यू के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के 68 युवाओं को हरी झंडी दिखाते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि आज के इस गौरवमय क्षण के साक्षी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री अरूण साव भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित अनेक लोग बने। भ्रष्टाचार पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जीरो टालरेन्स की नीति पर चल रही है। भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता मार्च में भाग ले रहे 68 युवाओं को विदा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के गौरव हैं, सिरमौर हैं। उनकी विकासशील नीतियों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ भी विकास के नए आयाम गढ़ रहा है।

विश्व विरासत सप्ताह का आयोजन लक्ष्मण मंदिर परिसर में विश्व विरासत सप्ताह का आयोजन

विश्व विरासत सप्ताह का आयोजन लक्ष्मण मंदिर परिसर में

रायपुर। विश्व विरासत सप्ताह का आयोजन आज सिरपुर स्थित प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर परिसर में उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विरासत संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गनवीर धम्मशील ने किया। विश्व विरासत सप्ताह 25 नवम्बर तक जारी रहेगा।

विश्व विरासत सप्ताह का आयोजन लक्ष्मण मंदिर परिसर में

श्री गनवीर ने सिरपुर की कला, स्थापत्य और पुरातात्विक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 7 वीं शताब्दी में निर्मित ईंट का यह मंदिर प्रारंभिक मंदिर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण में नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम में शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. कॉलेज, महासमुंद के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गईं। मंदिर परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी में भारत और छत्तीसगढ़ के एएसआई संरक्षित स्मारकों के छायाचित्र तथा सिरपुर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की गई। पारंपरिक संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों ने क्षेत्र की समृद्ध कला-संस्कृति को जीवंत किया।

विरासत का संरक्षण रहेगा जारी

विद्यार्थियों के लिए विरासत संरक्षण, नैतिकता तथा स्मारक सुरक्षा पर जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, स्थानीय निवासी, पर्यटक और धरोहर प्रेमियों ने सहभागिता दी। स्थानीय प्रशासन और सांस्कृतिक समूहों के सहयोग से आयोजन ज्ञानवर्धक, रोचक और सफल रहा। वर्ष भर विरासत संरक्षण के प्रयासों को जारी रखने का संकल्प लिया गया।

चौपाटी को हटाकर एजुकेशन हब विकसित करने की तैयारी, मूणत ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

रायपुर, साइंस कॉलेज मैदान के सामने बनी चौपाटी को अवैध बताते हुए भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि राज्य सरकार इस स्थान को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने जा रही है। उन्होंने बताया कि भूमि सरकारी होने के बावजूद बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के चौपाटी का निर्माण किया गया था। मूणत ने कहा कि दुकानदारों को हटाने के बजाय उनके पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया जारी है, जिससे किसी की आजीविका प्रभावित न हो। मूणत ने आरोप लगाया कि पूर्व भूपेश सरकार के कार्यकाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित यूथ हब और ग्रीन कॉरिडोर को बदलकर चौपाटी बना दी गई। उनका कहना है कि इससे राजनीतिक संरक्षण और व्यावसायीकरण साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इस स्थान पर लाइब्रेरी और अध्ययन हेतु शांत वातावरण तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जबकि कांग्रेस दुष्प्रचार कर शहरवासियों को भ्रमित कर रही है। विधायक ने कहा कि अवैध चौपाटी का मुद्दा पिछले साढ़े तीन वर्षों से उठाया जा रहा है और भाजपा ने निर्माण के विरोध में धरना और कानूनी प्रक्रिया दोनों का सहारा लिया। उन्होंने स्मार्ट सिटी के खर्च, टेंडर प्रक्रिया, लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन और अदालत में चली कार्यवाही के विवरण भी साझा किए। मूणत का कहना था कि यूथ हब में स्टेशनरी, पुस्तकें, मेडिकल, जिम उपकरण और अन्य शैक्षणिक जरूरतों से जुड़ी 60 दुकानें खोलने का प्रावधान था, लेकिन नियमों को दरकिनार कर फूड चौपाटी बना दी गई। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि निगम ने चौपाटी को नई जगह पर स्थानांतरित कर छात्रों के भविष्य को प्रभावित होने से बचाने का उचित कदम उठाया है। उन्होंने कांग्रेस पर झूठ फैलाने और शहर को गुमराह करने का आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में भाजपा संगठन के पदाधिकारी, नगर निगम प्रतिनिधि और कई पार्षद भी मौजूद रहे।

प्रोजेक्ट धड़कन संजय मित्तल ने दान की सात हार्ट चेकअप मशीनें

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा आंगनबाड़ी एवं स्कूली बच्चों के हृदय जांच हेतु प्रोजेक्ट धड़कन संचालित किया जा रहा है।यह प्रोजेक्ट सत्य साईं हॉस्पिटल, नवा रायपुर के सहयोग से संचालित हो रहा है। इसी क्रम में रायगढ़ के सिंघल स्टील उद्योग के श्री संजय मित्तल ने कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह से मुलाकात कर हृदय जांच के लिए सात हाई-डेफिनेशन स्टेथोस्कोप एवं टैबलेट दान किया । इन सात मशीनों में से चार मशीनें स्वास्थ्य विभाग तथा तीन मशीनें महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रदान की गई हैं।कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि अब तक जिले के 12,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों के बच्चों की जांच की जा चुकी है। इस योजना के तहत जिन बच्चों में हृदय संबंधी समस्या पाई जाती है, उन्हें आगे की जांच के लिए सत्य साईं हॉस्पिटल, नवा रायपुर भेजा जाता है। किसी भी बच्चे में गंभीर बीमारी की पुष्टि होने पर जिला प्रशासन द्वारा उसका निःशुल्क उपचार सुनिश्चित किया जाता है। कलेक्टर ने कहा, इस योजना का उद्देश्य है कि जिले का कोई भी बच्चा हृदय रोग से पीड़ित न रहे और सभी बच्चे स्वस्थ व सुरक्षित रहें। डॉ. सिंह ने कहा कि मशीनों की संख्या बढ़ने से हम जिले के हर बच्चे तक जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उनके सफल परीक्षण करवाएंगे । इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन, जिला पंचायत ईओ कुमार विश्वरंजन, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है : रंजना साहू

गृह ग्राम बिरेतरा में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना डीपेंद्र साहू ने ली बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 0में तेजी लाने पर हुई चर्चा

धमतरी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने अपने गृह ग्राम बिरेतरा पहुँचकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण स्ढ्ढक्र कार्यक्रम की प्रगति की विस्तृत जानकारी लेते हुए सभी ग्राम पंचायत पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशानिर्देश के साथ जानकारी भी दिए। बैठक में रंजना साहू ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए मतदाता सूची का सटीक व अद्यतन होना अत्यंत आवश्यक है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 04 दिसम्बर तक सभी मतदाताओं के फॉर्म संकलित कर ऑनलाइन अपलोड किए जाने हैं, अतः सभी बूथ स्तर के अधिकारियों, बीएलओ तथा कार्यकर्ताओं को यह कार्य अतिशीघ्र व पूरी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करना चाहिए। रंजना साहू ने कहा कि बूथ ही हमारे संगठन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है। प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में जुड़ना चाहिए और किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आप सभी कार्यकर्ता समयबद्ध तरीके से घर-घर पहुँचकर फॉर्म संकलित करें और सुनिश्चित करें कि 30 नवंबर से तक सभी विवरण ऑनलाइन अपलोड हो जाएँ, यह कार्य हमारी प्रतिबद्धता और संगठन की शक्ति दोनों को प्रदर्शित करता है। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाने, बूथ मजबूती के कार्यक्रमों में सक्रियता बढ़ाने तथा जनसंपर्क को निरंतर बनाए रखने का आह्वान किया। बैठक में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित प्रगति की जानकारी देते हुए आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से डीपेंद्र कुमार साहू,अजीत साहू,बूथ अध्यक्ष खिलू राम साहू एवं मनीष कुमार, बी एल ओ 2 मोहन कुमार एवं संतु राम सहित डॉ विनेश्वर साहू ,बिहारी लाल साहू,नूतन कुमार साहू,नीतेश्वर साहू, धन्नू तारक, पारथ राम साहू सहित कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।

गोगांव में जानलेवा हमले के मामले में आरोपी चिंटू बंजारे दोषी करार

संवाददाता

रायपुर, गोगांव थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई जानलेवा हमले की वारदात में आरोपी नीति श बंजारे उर्फ चिंटू को अदालत ने दोषी करार दे दिया है। मामले में आरोपी पर प्रार्थी रूखमणी महेश्वरी के दो बेटों–टीकम महेश्वरी और सूरज महेश्वरी–पर गंभीर हमला करने का आरोप साबित हुआ है। मामले के अनुसार 12 फरवरी 2022 की दोपहर लगभग चार बजे पुरानी पानी टंकी के पास आरोपी अपने साथी योगेश लहरे के साथ पहुंचा और टीकम महेश्वरी से विवाद करते हुए गाली-गलौज की। इसके बाद आरोपी ने धारदार हथियार से टीकम के कमर, पेट और सीने पर वार किए। वहीं बीच-बचाव करने आए सूरज महेश्वरी के सिर और कमर के नीचे भी चोट पहुंचाई गई। घटना के प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय लोग भी वहां मौजूद थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 62/2022 दर्ज किया और आरोपी व उसके साथी पर धारा 307, 323, 34 के तहत प्रकरण कायम किया। जांच में आरोपी के कब्जे से खून लगे कपड़े और लोहे का नुकीला चाकू जब्त किया गया, जिन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। घटनास्थल का पटवारी नजरी नक्शा भी तैयार किया गया। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नीति श बंजारे के खिलाफ धारा 294, 506(भाग-2), 307, 323, 326, 34 भा.दं.सं. के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद उसे दोषी ठहराया।

उपमुख्यमंत्री ने पुनर्वासित युवाओं के लिए मेडिकल कैम्प लगाने के दिए निर्देश

पुनर्वासित युवाओं के साथ उपमुख्यमंत्री ने लगाई चौपाल, खुद बैठकर युवाओं के बनवाये आधारभूत दस्तावेज

0सुकमा पुनर्वास केंद्र पहुंचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

सुकमा, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने शनिवार शाम सुकमा में बनाये गए पुनर्वास केन्द्र में आकस्मिक निरीक्षण किया। जहां उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे युवाओं के साथ चौपाल लगाकर उनसे बात की। इस दौरान पुनर्वासित युवाओं ने अपनी बातों को उपमुख्यमंत्री के सामने रखा। जहां उपमुख्यमंत्री खुद भी युवाओं के जमीन पर साथ बैठे और उनसे आत्मीय चर्चा की। उपमुख्यमंत्री की सरलता ने सभी को आनंदित कर दिया। सभी ने अपने मन की बातें बिना संकोच के उनके समक्ष रखी। इस दौरान उपमुख्यमंत्री शर्मा ने युवाओं से संवाद करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में आधारभूत व्यवस्थाओं के संबंध में युवाओं से सीधे जानकारी भी ली और अधिकारियों को उनके खाने और अन्य आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने युवाओं से शिक्षा और खेती एवं उनके परिवार सदस्यों से मुलाकात के संबंध में भी जानकारी ली। जहां पर उन्होंने अधिकारियों और पुनर्वासित युवाओं से कहा कि आपके परिजन यदि पुनर्वास केन्द्र में आकर मुलाकात करना चाहते हैं और यदि बाजार वाले दिन आकर जब भी मिलना चाहें तो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी पुनर्वासित युवा के परिवार जेल में निरूद्ध हैं और युवा उनसे मिलना चाहें तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने युवाओं में से यदि कोई विवाह की इच्छा भी रखते हैं तो उनके लिए भी सामूहिक विवाह की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुनर्वासित युवाओं ने अपने मूलभूत दस्तावेज पूर्ण ना होने की जानकारी दी। जिसपर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने तुरंत जिला प्रशासन के अधिकारियों को दस्तावेज निर्माण करवाने के निर्देश दिए। जिसमें उन्होंने स्वयं अधिकारियों के साथ बैठकर दस्तावेज निर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण किया और जहां भी दिक्कतें आईं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर उनका निराकरण भी किया। जहां आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड आदि बनवाने के लिए आवेदन कराए गए। उन्होंने युवाओं को विधानसभा सत्र के दौरान रायपुर भ्रमण कराकर उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी देने और उन्हें कार्यप्रणाली से अवगत कराने एवं इनके लिए पुनर्वास केंद्र में ही विशेष स्वास्थ्य शिविर लगवाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। उल्लेखनीय है कि सुकमा के पुनर्वास केंद्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पुनर्वासित युवाओं को राज मिस्त्री, कृषि उद्यमी, सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही पुनर्वास नीति के अनुसार उन्हें दीर्घकालिक रोजगार दिलाने हेतु सहायता भी दी जा रही है। इस अवसर पर एडीजी विवेकानंद सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, एसपी किरण चव्हाण, अपर कलेक्टर गजेंद्र सिंह ठाकुर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव का कांग्रेस पर हमला, एसआईआर प्रक्रिया को बताया पुरानी व्यवस्था

रायपुर,

प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल के बीच प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 24 नवंबर को रायपुर पहुंचने वाले हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस की बैठकों और समीक्षा पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विपक्ष बिना आधार के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। साव ने आरोप लगाया कि बिहार में भी कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर चुनावी माहौल गर्म किया था और वोट चोरी के आरोप लगाए थे, लेकिन जनता ने उसे स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, यह वर्षों से लागू है और कांग्रेस जनसमर्थन खोने के बाद अब भ्रम फैलाकर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है। साव का कहना है कि जैसे बिहार में जनता ने जवाब दिया, वैसे ही अन्य राज्यों में भी होगा।

रायपुर में अंतरराष्ट्रीय वनडे से उत्साह

उपमुख्यमंत्री ने 3 दिसंबर को रायपुर में होने वाले भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे को लेकर भी उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर क्रिकेट प्रेमियों की मौजूदगी के बीच यह मैच होना राज्य के लिए गौरव की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मुकाबला छत्तीसगढ़ के लिए एक यादगार अवसर बनेगा।

18 ठिकानों पर रेड–साव का बयान

प्रदेश में आबकारी और ष्ठरूस्न घोटाले से जुड़े मामलों में सीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा करीब 18 स्थानों पर की गई कार्रवाई पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इन मामलों की जांच पहले से प्रगति पर थी। उन्होंने बताया कि जो कदम उठाए जा रहे हैं, वे जांच एजेंसियों के निष्कर्षों के आधार पर हैं और प्रक्रिया नियमों अनुसार आगे बढ़ रही है।

डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर तैयारियां

साव ने बताया कि इस वर्ष डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को मेजबानी दी है। देशभर के शीर्ष पुलिस अधिकारी एक ही मंच पर रणनीति और आगामी सुरक्षा दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। उन्होंने इसे राज्य के लिए महत्वूर्ण और ऐतिहासिक आयोजन बताया।

साइंस कालेज के समीप से आमानाका आरओबी के समीप नये वेंडिंग जोन में शिफ्ट किये गये चौपाटी वेंडरो ने महापौर मीनल चौबे से की मुलाकात

स्मार्ट सिटी का एग्रीमेंट मेसर्स हरिकिशन होटल एंड रिसोर्ट के साथ हुआ है.अधिकारी सुनिश्चित करेंकि एग्रीमेंट के शर्तों का पालन हो

चौपाटी संचालक के किरायेदार मेरे शहर की सम्मानित जनता.उनकी पूरी चिंता हम करेंगे और यथासंभव मदद करेंगे

महापौर मीनल ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों को नगर निगम के साथ मिलकर आमानाका आरओबी के समीप नए वेंडिंग जोन में वेंडर्स को सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा व्यवस्था का फोकस कर पुख्ता प्रबंध शीघ्र दिलवाने दिए निर्देश

रायपुर (लोकशक्ति)।

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा राजधानी शहर जीई मार्ग के किनारे साइंस कालेज के समीप से आमानाका रेल्वे ओव्हर ब्रिज के समीप निर्धारित नवीन वेंडिंग जोन में शिफ्ट किये गये चौपाटी वेंडरो ने आज नगर निगम रायपुर मुख्यालय पहुंचकर महापौर मीनल चौबे से उनके कार्यालयीन कक्ष में मुलाकात की एवं नये वेंडिंग जोन को शीघ्र सुविधा युक्त बनवाने का अनुरोध किया।

महापौर मीनल चौबे ने ध्यानपूर्वक चौपाटी वेंडरो की बातो को सुना और महापौर कक्ष में उपस्थित रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के उपप्रबंधक और रायपुर नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन अभियंता अंशुल शर्मा जुनियर, निगम सहायक अभियंता शैलेन्द्र पटेल, स्मार्ट सिटी सहायक प्रबंधक निगम उपअभियंता शुभम तिवारी, योगेन्द्र साहू को निर्देशित किया कि नये वेंडिंग जोन आमानाका आरओबी के समीप साइंस कालेज के समीप के वेंडिंग जोन से शिफ्ट किये गये चौपाटी वेंडरो को वहां प्राथमिकता से फोकस करते हुए सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाईट और सुरक्षा व्यवस्था की सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवाना रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा रायपुर नगर पालिक निगम के संबंधित अधिकारियों से समन्वय रखकर सुनिश्चित किया जाये ताकि यह चौपाटी वेंडर्स के लिए सुविधायुक्त वेंडिंग जोन बना रहे। सफ ई, पेयजल, स्ट्रीट लाईट, सुरक्षा व्यवस्था कायम कर प्रशासनिक तौर पर उसकी सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये ताकि नये वेंडिंग जोन में जाने वाले नगरवासियो को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। भविष्य में आमानाका आरओबी समीप के नये वेंडिंग जोन का व्यवहारिक आवश्यकता के अनुरूप सौंदर्याकरण करने आवश्यक प्रस्ताव सर्वे आदि कर तैयार किया जाये ताकि उसे जन अपेक्षित रूप से भविष्य में आने वाले समय में सुन्दर स्वरूप दिया जा सके। महापौर ने चौपाटी वेंडर्स से कहा कि वे नये वेंडिंग जोन में अपना व्यवसाय शीघ्र प्रारंभ करें ताकि नागरिको को शीघ्र अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके।

कलेक्टर पहुंचे धान खरीदी केन्द्र, जांची केन्द्र की व्यवस्था

एनआईएफ टीईएम ने दिया मोटे अनाज से बेकरी उत्पाद निर्माण का जशपुर में प्रशिक्षण

पोषण तत्वों के साथ ही रोजगार के अवसरों की दी जानकारी

रायपुर,संवाददाता ।

एनआईएफ़टीईएम के छात्रों ने मोटे अनाज में पाए जाने वाले फ़ाइबर, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के महत्व के साथ ही इनके नियमित उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य लाभों पर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागी महिलाओं को मोटे अनाज आधारित उत्पादों से होने वाली आमदनी और बाज़ार संभावनाओं के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षण में स्व-सहायता समूह की 25 महिलाओं की रही सहभागिता हरियाणा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट द्वारा महुआ पर स्थापित सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में विगत दिवस मोटे अनाज के पोषण तत्वों और इनके उपयोग से बेकरी उत्पाद बनाने संबंधी हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण में स्व सहायता समूह की 25 महिलाओं ने सहभागिता की। मोटे अनाज का उपयोग बढ़ाकर पोषण स्तर में करना है वृद्धि कार्यक्रम का उद्देश्य नान खटाई, न्यूट्रीबार, कुकीज़ जैसे बेकरी आइटम्स में मोटे अनाज का उपयोग बढ़ाकर इनके पोषण स्तर में वृद्धि करना और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। यह प्रशिक्षण जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। स्थानीय समुदायों को खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्यमिता से है जोड़ना जशपुर में एनआईएफ़टीईएम टीम वैल्यू-एडेड फूड प्रोडक्ट्स के उत्पादन के साथ-साथ पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। यह पूरी पहल स्थानीय समुदायों को खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ।

धान खरीदी में आई तेजी, किसान बिना परेशानी के बेच रहे हैं धान

0 बेहतर व्यवस्थाओं से उपार्जन केंद्रों में बढ़ी किसानों की भीड़

0 टोकन तुहर हाथ ऐप से धान खरीदी प्रक्रिया हुई आसान

रायपुर, । छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला बिना किसी व्यवधान के जारी है। धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक तेज से होने लगी है। सभी समितियों एवं उपार्जन केंद्रों में धान लेकर आने वाले किसानों से बिना किसी रूकावट के धान खरीदी की जा रही है। टोकन तुहर हाथ ऐप द्वारा ऑनलाइन टोकन कटने से लेकर धान तौलाई तक की संपूर्ण प्रक्रिया बेहद ही आसान और सुविधाजनक है। बिलासपुर जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में किसान अब बड़ी संख्या में अपने धान बेचने आ रहे हैं। केंद्रों में शेड, पेयजल, लाइट सहित बारदाने की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। क्षेत्र के किसानों की सकारात्मक प्रक्रिया ने केंद्रों की व्यवस्थाओं को पारदर्शी साबित किया है। मस्तूरी विकासखंड के जयरामनगर धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने आए किसान संजय पाण्डे ने बताया कि वे लगभग 4 से 5 एकड़ में धान की खेती करते हैं एवं प्रतिवर्ष यहां धान बेचने आते हैं। आज उनके टोकन का नंबर लगा है, उन्हें टोकन कटवाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आयी है। वे केंद्र की व्यवस्थाओं से पूरी तरह संतुष्ट है।

इसी प्रकार खैरा से धान बेचने आए किसान तीजराम साहू ने बताया कि वे 134 कट्टी धान लेकर समिति में धान बेचने पहुंचे हैं। आसानी से टोकन कटा और उनका धान भी समर्थन मूल्य पर विक्रय हो गया है। अब वे बिना किसी चिंता के घर जा सकते हैं। धान उपार्जन केंद्र में अच्छी गुणवत्ता के बारदाने उपलब्ध हैं और यहां के कर्मचारियों का व्यवहार भी सहयोगपूर्ण रहा। उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी के साथ ही अब जिले के उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की रफ्तार बढ़ी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की किसान-केंद्रित नीतियों और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता ने तस्वीर बदल दी है।

डीएमएफऔर शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू की टीम ने 8 जिलों में की छापेमारी

महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद

लोकशक्ति

रायपुर, छत्तीसगढ़ में रविवार सुबह ईओडब्ल्यू (राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) की टीम ने रायपुर, बिलासपुर समेत 8 जिलों में एक साथ छापेमारी की। डीएमएफ और शराब घोटाले से जुड़े मामलों में हुई इस कार्रवाई से प्रदेश में हड़कंप मच गया। वहीं ईओडब्ल्यू ने प्रेस रिलीज़ जारी कर पूरे कार्रवाई की जानकारी साझा की है। ईओडब्ल्यू के अनुसार, रविवार को डीएमएफ घोटाला और शराब घोटाला प्रकरणों में दर्ज मामलों के आधार पर राज्य के कुल 19 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। डीएमएफ घोटाले से जुड़े अपराध क्रमांक 02/2024 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, 12 तथा आईपीसी की धारा 420, 120(बी) के तहत कार्रवाई की गई। इस मामले में हरपाल सिंह अरोड़ा और उनसे जुड़े व्यक्तियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी जिन जिलों में हुईः रायपुर - 4 स्थान बिलासपुर - 2 स्थान सरगुजा - 2 स्थान कोंडागांव - 1 स्थान धमतरी - 1 स्थान बलरामपुर - 1 स्थान कुलः 11 स्थान शराब घोटाला : 8 स्थानों पर की गई कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़े अपराध क्रमांक 04/2024 में भ्र.नि.अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, 12 तथा आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120(बी) के तहत छापेमारी की गई। इस मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी अनिल टुटेजा और निरंजन दास के परिजनों से जुड़े ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की गई। छापेमारी जिन जिलों में हुईः बिलासपुर - 4 स्थान रायपुर - 2 स्थान दुर्ग -1 स्थान बस्तर - 1 स्थान कुलः 8 स्थान महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद सर्च ऑपरेशन के दौरान ईओडब्ल्यू ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए हैं। अधिकारियों के अनुसार, जब्त सामग्री को अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल कर आगे की विवेचना जारी है।

चौपाटी विवाद पर भाजपा ने रखा अपना पक्ष, कहा अवैध रूप से बनाई गई

रायपुर, राजधानी में बढ़ते चौपाटी विवाद के बीच भाजपा ने एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस अयोजित कर अपना पक्ष रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने साइंस कॉलेज ग्राउंड से चौपाटी हटाने के कारणों की जानकारी दी। राजेश मूणत ने कहा कि यह मामला अभी का नहीं है, बल्कि साढ़े 3 साल पुराना है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान भी भाजपा लगातार इस अवैध निर्माण का विरोध करती रही है। मूणत ने कहा कि स्मार्ट सिटी ने चौपाटी को यूथ हब बताकर बनाया, जबकि यह जमीन नगर निगम की नहीं बल्कि खेल विभाग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के तमाम नेताओं ने इस अवैध चौपाटी के निर्माण के विरोध में 12 दिन प्रदर्शन किया था। दुकानों के संचालन के लिए एजेंसी को 29 लाख में दिया गया, जबकि 60 दुकानों से मासिक 25 हजार लिए जा रहे थे।

दवाइयों पर 'एक राष्ट्र-एक दाम' की मांग उठाने वाले देश के पहले सांसद बने बृजमोहन

एक्सपायरी दवाओं के राष्ट्रीय निस्तारण नीति की जोरदार वकालत-सांसद बृजमोहन ने उठाई मरीजों की सुरक्षा की बड़ी बात

बीजापुर व रायपुर की घटनाओं पर गंभीर चिंता—एक्सपायर दवा नष्ट करने की जिम्मेदारी कंपनियों पर तय हों: सांसद अग्रवाल

अस्पतालों में दवाइयों की पारदर्शी खरीदी व्यवस्था की दिशा में बड़ा सुझाव—केंद्र स्तर पारदर्शी सिस्टम की मांग

रायपुर/नई दिल्ली (संवाददाता)। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने दवाइयों पर 'एक राष्ट्र-एक दाम' की मांग की है।सोमवार को नई दिल्ली में रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने तथा आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कई मौलिक, दूरदर्शी और जनकल्याणकारी सुझाव रखे, जिन्हें समिति ने अत्यंत गंभीरता से सुना।

बैठक में देश में दवाओं की कीमतों में वृद्धि के विशेष संदर्भ में एनपीपीए की भूमिका, कार्यों और कर्तव्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान औषध विभाग एवं एनपीपीए के उच्च अधिकारियों ने समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया।

देश में दवाइयों के 'एक राष्ट्रएक दाम' की आवश्यकता पर जोर

बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में अलग-अलग राज्यों में दवाइयों की खरीद अलग-अलग दरों पर होती है, जिससे न केवल व्यवस्था जटिल होती है बल्कि मरीजों की सुविधा भी प्रभावित होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि, ÷देश में दवाइयों की खरीदी का सिस्टम एक जैसा हो और केंद्र स्तर पर एकीकृत व्यवस्था बने। इससे पूरे देश में दवाइयों का एक दाम तय हो और राज्यों को बार-बार अलग-अलग टेंडर नहीं करने पड़ें। यह व्यवस्था मरीजों को दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और पारदर्शिता को बढ़ाएगी।÷ उनका यह सुझाव स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़े सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एक्सपायरी दवाओं के निस्तारण की राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव - सांसद अग्रवाल ने देशभर के सरकारी अस्पतालों में बड़ी मात्रा में पड़ी एक्सपायरी दवाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि, ÷एक्सपायरी दवाओं का उचित निस्तारण नहीं होने से पर्यावरण, मिट्टी और जल स्रोत गंभीर रूप से प्रदूषित होते हैं। अतः केंद्र सरकार को ऐसी दवाओं को वापस लेने और नष्ट करने के लिए कंपनियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए।÷ उन्होंने साफ कहा कि एक्सपायर दवाओं को खुले में फेंकना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा जोखिम है।

बिजापुर और रायपुर की घटनाओं का संज्ञान - बैठक में सांसद ने अक्टूबर माह में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की दृष्टि जाने तथा रायपुर में 9 लोगों की आंखें खराब होने की घटनाओं को गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा ÷यदि दवा एक्सपायर है, तो उसके लिए वही कंपनी जिम्मेदार होगी। ऐसी दवाओं के निस्तारण और जवाबदेही की सख्त नीति अनिवार्य है। मरीजों की जिंदगी से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है।÷

सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा उठाए गए ये मुद्दे यह दर्शाते हैं कि वे न केवल अपने संसदीय क्षेत्र बल्कि पूरे देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत एवं सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर सक्रिय और संवेदनशील हैं। समाज के सबसे कमजोर वर्ग, मरीजों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देना उनके समर्पित जनप्रतिनिधित्व का प्रमाण है।

एनआईएफटीईएम ने दिया मोटे अनाज से बेकरी उत्पाद निर्माण का जशपुर में प्रशिक्षण

पोषण तत्वों के साथ ही रोजगार के अवसरों की दी जानकारी

रायपुर, एनआईएफ़टीईएम के छात्रों ने मोटे अनाज में पाए जाने वाले फ़ाइबर, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के महत्व के साथ ही इनके नियमित उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य लाभों पर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागी महिलाओं को मोटे अनाज आधारित उत्पादों से होने वाली आमदनी और बाज़ार संभावनाओं के बारे में भी बताया गया।प्रशिक्षण में स्व-सहायता समूह की 25 महिलाओं की रही सहभागिताहरियाणा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट द्वारा महुआ पर स्थापित सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में विगत दिवस मोटे अनाज के पोषण तत्वों और इनके उपयोग से बेकरी उत्पाद बनाने संबंधी हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण में स्व सहायता समूह की 25 महिलाओं ने सहभागिता की।मोटे अनाज का उपयोग बढ़ाकर पोषण स्तर में करना है वृद्धि कार्यक्रम का उद्देश्य नान खटाई, न्यूट्रीबार, कुकीज़ जैसे बेकरी आइटम्स में मोटे अनाज का उपयोग बढ़ाकर इनके पोषण स्तर में वृद्धि करना और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। यह प्रशिक्षण जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। स्थानीय समुदायों को खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्यमिता से है जोड़ना जशपुर में एनआईएफ़टीईएम टीम वैल्यू-एडेड फूड प्रोडक्ट्स के उत्पादन के साथ-साथ पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। यह पूरी पहल स्थानीय समुदायों को खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से चलाए जा रहा है। यह प्रशिक्षण जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। स्थानीय समुदायों को खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्यमिता से है जोड़ना जशपुर में एनआईएफ़टीईएम टीम वैल्यू-एडेड फूड प्रोडक्ट्स के उत्पादन के साथ-साथ पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। यह पूरी पहल स्थानीय समुदायों को खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से कार्यक्रम का अंतर्गत की जा रही है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रो. प्रसन्ना कुमार जी.वी. और अभिमन्यु गौर कर रहे हैं, जबकि यह कार्यक्रम एनआईएफ़टीईएम के डायरेक्टर डॉ. हरिंदर सिंह ओबेरॉय के निर्देशन में संचालित हो रहा है। कार्यक्रम के संचालन और विभिन्न गतिविधियों के समन्वय में मिशन मैनेजर विजय शरण प्रसाद और जय जंगल एफ्पीसी जशपुर के डायरेक्टर समर्थ जैन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

रायपुर में सभी संपत्तियों का नया हाई-टेक सर्वे, 60 हजार तक नई संपत्तियां टैक्स दायरे में आने की संभावना

रायपुर,। राजधानी में नगर निगम अब शहर की सभी संपत्तियों का नया, व्यापक और तकनीक आधारित सर्वे शुरू करने जा रहा है। निगम सूत्रों के अनुसार, महीने के अंत तक सर्वे का औपचारिक शुभारंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए एक निजी सर्वे कंपनी से अनुबंध की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वर्क ऑर्डर जारी होते ही टीम घर-घर पहुंचकर संपत्तियों का डेटा जुटाएगी, जिससे अब तक रिकॉर्ड से बाहर संपत्तियों को टैक्स सिस्टम में शामिल किया जा सके। नगर निगम ने पिछली बार वर्ष 2017-18 में विश्व बैंक की सहायता से जीआईएस तकनीक के माध्यम से सर्वे कराया था, जिसमें लगभग 3.52 लाख संपत्तियों को सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन इसके बाद शहर के तेज विस्तार के चलते नए मकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मल्टीस्टोरी कॉम्प्लेक्स और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट तेजी से बढ़े। निगम का अनुमान है कि करीब 50 से 60 हजार नई संपत्तियां अभी तक दर्ज नहीं हो पाई हैं। इस बार ड्रोन की जगह रडार आधारित 3डी सर्वे की तकनीक अपनाई जाएगी। इस तकनीक से भवनों की ऊंचाई, मंजिलों की संख्या, संरचना और स्थलाकृति का सटीक त्रि-आयामी नक्शा तैयार होगा। इससे भविष्य में सिवरेज, पेयजल, सड़क और शहरी ढांचा विकास की प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। परियोजना लागत पहले 60 करोड़ रूपए आंकी गई थी, पर नई तकनीक के कारण लगभग 2 करोड़ की अतिरिक्त लागत आएगी। निगम ने 10 कंपनियों से टेक्निकल प्रेजेंटेशन लेकर ड्रोन, रडार और सैटेलाइट सर्वे की तुलना की।

संपादकीय

भारत के खिलाफ साजिशों करता पाक

बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों के साथ गहराते रिश्तों के कारण पाकिस्तान के लिए भारत विरोधी साजिश रचना और आसान हो गया है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक भारत में इस वर्ष अब तक आतंकवाद से संबंधित साजिश के आरोप में 82 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसे इस बात का संकेत समझा गया है कि आतंक का नेटवर्क फिर फैल रहा है, जो हाल के वर्षों में कमजोर पड़ा हुआ था। इसके पीछे पाकिस्तान संचालित गुटों के हाथ का संदेह है। इसके बावजूद पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ी है, तो उसके पीछे डॉनल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका का रुख एक प्रमुख कारण है। चीन का समर्थन तो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा ही है।

मौन के शब्दों की मिठास

मौन कभी-कभी
एक पका हुआ फल
जिसे दबाओ तो
खटास नहीं,
मीठा-सा रस टपकता है।

बोलने से पहले
शब्द
मौन के भीतर
पकते रहते हैं,
जैसे किसी अनदेखे खेत की
भीगी मिट्टी में
बीज अपने समय का
इंतज़ार कर रहे हों।

हम सोचते
कि सच बोलने से मिलता
पर सच तो अक्सर
मौन के घर बैठा
एक अदृश्य दीपक होता
जैसे बिना लौ के
किसी कमरे को
हल्का-हल्का उजाला मिल रहा हो।

मौन
दूर से
थोड़ा भारी लगता ,
पर पास जाकर देखो
तो वह उतना ही हल्का होता
जितना किसी बच्चे के हाथ में
छिपा हुआ
एक बिना बोला सवाल।

कभी कोई
साधारण-सी दोपहर
जब हवा बिल्कुल धीमी चलती ,
तो ऐसा लगता है
जैसे मौन
हमारे कंधे पर
अपना सिर रखकर
कह रहा हो—
यह जो शांत है,
यही मीठा है।

और फिर
हम समझते
कि हर शब्द
जिसे हमने कहा नहीं,
वही हमारे भीतर
सबसे ज़्यादा
मधुरता से
गूँज रहा। **संजीव ठाकुर,**

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा
लिखित पुस्तकें पढ़िये
ऑनलाईन

PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp
Modimaya_ Vaidik_Netritva
Rashtriya Ekta
DLF-Vadra-Bhrasht Tantra
Silent Assassins Jan11,1966
Accursed & Jihadi Neighbour

जी-20 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी के सुझावों की रोशनी

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

जी-20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सत्र इस बार जिस गंभीर मुद्दे पर केन्द्रित रहा, वह दुनिया के सामने उभरते खतरों की बदलती प्रकृति को स्पष्ट करता है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के साथ-साथ ड्रग तस्करी को भी वैश्विक शांति, सुरक्षा और मानव अस्तित्व के लिए उतना ही घातक बताया जितना किसी संगठित हिंसा को माना जाता है। उनकी यह चेतावनी केवल कूटनीतिक वक्तव्य नहीं बल्कि बढ़ती वैश्विक वास्तविकताओं का सटीक विश्लेषण है। यह तथ्य अब निर्विवाद है कि मादक पदार्थों की तस्करी आतंकवाद को ईंधन प्रदान करने वाला सबसे बड़ा स्त्रोत बन चुकी है। अरबों डॉलर का यह अवैध व्यापार केवल अपराध जगत को नहीं बल्कि राष्ट्रों की सुरक्षा, समाज की स्थिरता और युवाओं के भविष्य को भी चूर-चूर कर रहा है।

मोदी ने अपने संबोधन में साफकहा कि दुनिया के बड़े राष्ट्रों को ड्रग-माफिया और उसके आतंकवाद से जुड़े वित्तीय नेटवर्क के खिलाफएकजुट होकर निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। दुनिया आज जिस गति से नए-नए मादक पदार्थों के जाल में फंसती जा रही है, वह वैश्विक चिंता और भी बढ़ाता है। फेंटानाइल जैसे अत्यंत खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स ने अमेरिका में स्वास्थ्य-संकट की भयावह स्थिति पैदा कर दी है, जहां प्रतिदिन अनेक लोग इसके कारण जान गंवा रहे हैं। यह संकट किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि मानव जीवन पर मंडरा रहा एक वैश्विक खतरा है। यह मानना भूल होगी कि ऐसे ड्रग्स केवल एक महाद्वीप तक सीमित रह सकते हैं; संगठित तस्करी के नेटवर्क इसकी पहुंच दुनिया के किसी भी कोने तक ले जा सकते हैं। यही कारण है कि मोदी ने चेताया कि यदि अभी निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, तो यह त्रासदी अन्य देशों में भी फैल सकती है।

ड्रग्स माफिया केवल एक आपराधिक व्यापार नहीं, बल्कि मानव समाज की जड़ों को खोखला करने वाला वैश्विक संकट है। नशे का कारोबार सीमाओं, कानूनों और नैतिक मूल्यों-तीनों को धत्ता बताकर फैल रहा है। यह न केवल युवाओं के भविष्य को निगल रहा है, बल्कि देशों की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक व्यवस्था को भी कमजोर कर रहा है। इसलिए ड्रग्स माफिया का खतरा अब केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। दुनिया भर में नशे का अवैध व्यापार एक विशाल संगठित नेटवर्क के रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें माफिया, कार्टेल, हथियार गिरोह, आतंकवादी संगठन और भ्रष्ट तंत्र की गहरी सांठगांठ शामिल है। यह नेटवर्क इतना शक्तिशाली है कि कई देशों में यह समानान्तर सत्ता जैसा व्यवहार करता है। अफगानिस्तान, मैक्सिको, कोलंबिया, म्यांमार, नाइजीरिया, रूस और यूरोप तथा एशिया के अनेक हिस्सों में ड्रग्स कार्टेलों ने शासन प्रणालियों को चुनौती दी है। अनेक जगह तो स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि सरकारें या तो इस लड़ाई में कमजोर पड़ जाती हैं या फिर समझौते करने को मजबूर हो जाती हैं। मोदी ने इस पर नियंत्रण के लिये दुनिया को एकजुट होने की आवश्यकता व्यक्त की।

जी-20 देशों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे ड्रग्स के अवैध उत्पादन, वितरण, ऑनलाइन डार्क-नेट व्यापार, क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से होने वाले भुगतान और सीमा-पार तस्करी पर न केवल नियंत्रण करें बल्कि इसके खिलाफ साझा रणनीति भी अपनाएं। मोदी ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए-प्रत्येक देश में अवैध वित्तीय गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण, एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास, डेटा साझाकरण को बढ़ावा, तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करना तथा डिजिटल और साइबर अपराधों के विरुद्ध नई वैश्विक नीति बनाना। एआई का दुरुपयोग आज केवल गलत सूचना फैलाने या साइबर अपराध तक सीमित नहीं रहा; उसके माध्यम से ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री, नकली पहचान, एन्क्रिप्टेड चैनल और तस्करों के गुप्त नेटवर्क को चलाने में भी व्यापक उपयोग होने लगा है। इस पर रोक अब सामूहिक प्रयासों के बिना संभव नहीं।

इस वर्ष का जी-20 शिखर सम्मेलन अमेरिका की अनुपस्थिति के बावजूद काफी सफल माना गया। यह सफलता केवल उपस्थिति की संख्या में नहीं बल्कि चर्चाओं की गुणवत्ता, मुद्दों की गंभीरता और लिए गए निर्णयों के ठोस स्वरूप में दिखाई दी। बड़े देशों का एक-दूसरे से समन्वय और वैश्विक चुनौतियों को लेकर स्पष्टता इस सम्मेलन की बड़ी उपलब्धि रही। दुनिया का बदलता भू-राजनीतिक वातावरण, यूक्रेन और मध्य-पूर्व जैसे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और ग्लोबल साउथ की महत्वाकांक्षाएं-इन सबके बीच भी यह सम्मेलन शांत, रचनात्मक और समाधान-उन्मुख रहा। यह संकेत है कि दुनिया के राष्ट्र अब प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सहयोग को प्राथमिकता देने लगे हैं। ड्रग-तस्करी और आतंकवाद जैसे मुद्दे किसी भी देश की सीमाओं में बंधे नहीं रह सकते; इसलिए उनका समाधान भी सीमाओं के पार सहयोग से ही संभव है।

मोदी के सुझावों का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत लंबे समय से सीमा-पार आतंकवाद का शिकार रहा है और दक्षिण एशिया में ड्रग-तस्करी का एक बड़ा ट्रांज़िट-पॉइंट भी बनता रहा है। भारत ने तकनीक, कानून और कूटनीति-तीनों स्तरों पर इस खतरे से मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनसे दुनिया सीख सकती है। भारत का अनुभव बताता है कि ड्रग-नेटवर्क को समाप्त करने के लिए तीन मोर्चों पर काम करना अत्यंत आवश्यक है-कड़ी सीमा निगरानी, सोशल-मीडिया एवं एआई आधारित निगरानी तंत्र को मजबूत करना, और युवाओं में नशामुक्ति एवं जागरूकता को बढ़ाना। केवल कानून पर्याप्त नहीं; सामाजिक-मानसिक जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है।

जी-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय, प्रभावशाली और केंद्रीय उपस्थिति ने एक बार फिर सिद्ध किया कि वे आज वैश्विक परिदृश्य के सबसे सशक्त, निर्णायक और भरोसेमंद नेताओं में अग्रणी हैं। अमेरिका की अनुपस्थिति के बावजूद विश्व मंच पर नेतृत्व का जो शून्य बन सकता था, उसे मोदी ने अपने संयमित, दूरदर्शी और कूटनीतिक करिश्मे से भर दिया। ड्रग-तस्करी, आतंकवाद, एआई के दुरुपयोग, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल साउथ और मानव-कल्याण जैसे विविध मुद्दों पर उनकी स्पष्ट दृष्टि और व्यावहारिक समाधान ने दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि भारत न केवल उभरती शक्ति है बल्कि स्थिर और सकारात्मक दिशा दिखाने वाला पथ-प्रदर्शक भी है। उनकी उपस्थिति ने यह भी रेखांकित किया कि बदलती वैश्विक राजनीति में जहां कई राष्ट्र आंतरिक संघर्षों और नीतिगत अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं, वहीं भारत एक विश्वसनीय, स्थिर और दूरदर्शी नेतृत्व प्रस्तुत कर रहा है। मोदी का यह उभार केवल भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा नहीं उठाता बल्कि दुनिया को एक ऐसे नेतृत्व का विकल्प देता है जो विकास, शांति, सुरक्षा और वैश्विक सहयोग के नए मॉडल को आगे बढ़ा सकता है और यही आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ÷एकात्म मानववाद÷ के दर्शनशास्त्र को वैश्विक विकास के भविष्य में महत्वपूर्ण बताते हुए दुनिया से इसे अपनाने की अपील की। मोदी ने पारंपरिक ज्ञान, स्वास्थ्य क्षेत्र, क्रिटिकल मिनरल्स, सैटेलाइट डेटा एक्सेस, अफ्रीका में क्षमता निर्माण और ड्रग-टेरर नेटवर्क के खिलाफसंयुक्त कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि इससे दीर्घकालिक शांति, मज़बूती और सतत विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्षता की प्रशंसा की, जिसने कौशल आधारित प्रवासन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने यह भी बताया कि नई दिल्ली जी-20 शिखर सम्मेलन में लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों पर आगे कार्य हो रहा है। जी-20 शिखर सम्मेलन का संकेत स्पष्ट है: दुनिया अब नए खतरे पहचान रही है और उन पर सामूहिक कार्रवाई के लिए तैयार भी हो रही है। आतंकवाद और ड्रग-तस्करी के गहरे रिश्ते को तोड़ना वैश्विक शांति के लिए अनिवार्य है। यदि आर्थिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित समाज बनाना है, तो ड्रग-पर नियंत्रण करना ही होगा। दुनिया की बढ़ती असुरक्षा का मुकाबला केवल हथियारों से नहीं, बल्कि जागरूकता, संयम, शिक्षा और संवेदनशीलता से होगा। जब तक हम नशे के इस वैश्विक खतरे को एक सामूहिक लड़ाई न मानें, तब तक सुरक्षा केवल एक भ्रम बनी रहेगी। समाज को नशे के खिलाफखड़ा करना आज समय की बड़ी मांग है-क्योंकि यह केवल एक अपराध के खिलाफसंघर्ष नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य देने का संकल्प है।

यह निजी विचार है।

दुनिया अब अमेरिका पर निर्भर नहीं, ये अहसास विश्व को कराया

-नीरज कुमार दुबे

जी-20 शिखर सम्मेलन से जहाँ अमेरिका गायब था, वहाँ भारत सक्रिय था। जहाँ पश्चिमी देश मौन थे, वहाँ भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई। जहाँ त20 नेतृत्व की विफलता दिख रही थी, वहाँ मोदी ने IBSA और G20 के बीच पुल का काम किया।

दक्षिण अफ्रीका में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन ने वैश्विक राजनीति का एक कटु, किंतु स्पष्ट सत्य उजागर कर दिया कि दुनिया अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रही। यह वह क्षण था जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अपनी जिम्मेदारियों से अनुपस्थित रही और एक विकासशील राष्ट्र भारत ने अपने नेतृत्व, संतुलन और परिपक्वता से पूरे शिखर सम्मेलन की धुरी बदल दी। अमेरिका की गैर-हाज़िरी केवल एक प्रोटोकॉल त्रुटि नहीं थी; यह वैश्विक व्यवस्था में उसकी गिरती साख का सार्वजनिक प्रदर्शन था। दक्षिण अफ्रीका ने जिस स्पष्टता से यह कह दिया कि वह अपने राष्ट्रपति के सम्मान में किसी जूनियर अमेरिकी अधिकारी को बैटन नहीं सौंप सकता, वह अमेरिकी कूटनीति के लिए एक सीधा और तीखा संदेश था। और जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि ÷दुनिया अमेरिका के बिना भी आगे बढ़ सकती है÷, तो यह वह वाक्य था जिसे दस वर्ष पहले सोचना भी कठिन था। परंतु इस पूरे परिदृश्य से यदि किसी की भूमिका सबसे अधिक उभरी तो वह थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।

जहाँ अमेरिका गायब था, वहाँ भारत सक्रिय था। जहाँ पश्चिमी देश मौन थे, वहाँ भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई। जहाँ G20 नेतृत्व की विफलता दिख रही थी, वहाँ मोदी ने IBSA और G20 के बीच पुल का काम किया। IBSA बैठक में प्रधानमंत्री का यह कहना कि UNSC सुधार अपरिहार्य है, आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं, ग्लोबल साउथ को सामूहिक आवाज़ चाहिए, केवल भारतीय रुख नहीं था; यह आज की वैश्विक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता था। यह बात दुनिया देख रही है कि भारत केवल मुद्दों पर बात नहीं करता, भारत समाधान लेकर आता है।

हम आपको बता दें कि अमेरिका की अनुपस्थिति ने ज्यों ही एक रिक्तता पैदा की, मोदी की लगातार द्विपक्षीय बैठकें इस बात का स्पष्ट प्रमाण बन गईं कि दुनिया भारत को स्थिर नेतृत्व के रूप में देखती है। जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची से मुलाकात केवल औपचारिकता नहीं थी; यह भारत-जापान Special Strategic Partnership को नई ऊर्जा देने का क्षण था। AI, सेमीकंडक्टर, रक्षा और इंडो-पैसिफिक, इन सभी महत्वपूर्ण आयामों में दोनों देशों का सहयोग एशिया के लिए निर्णायक होगा।

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ हुई बातचीत में India–Italy Initiative to Counter Terror Financing का अपनाया जाना यह दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक आतंकवाद-रोधी ढांचे का नेता बन चुका है। वहीं काफी तनावपूर्ण पृष्ठभूमि के बावजूद कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बातचीत का सकारात्मक और उत्पादक होना भारत की कूटनीतिक परिपक्वता का प्रमाण है। CEPA वार्ता का फिर शुरू होना दोनों देशों के संबंधों में नया आत्मविश्वास दर्शाता है। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने यह पुनः स्थापित किया कि भारत और दक्षिण अफ्रीका केवल साझेदार नहीं, बल्कि उभरते वैश्विक दक्षिण के नेतृत्वकर्ता हैं। AI, टेक्नोलॉजी और भविष्य की अर्थव्यवस्था का वैश्विक एजेंडा भारत तय कर रहा है। साथ ही G20 के तकनीकी सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह मानव-केंद्रित AI का विज़न रखा, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत केवल अपनी तकनीकी ताकत नहीं दिखा रहा, बल्कि यह बता रहा है कि आने वाली दुनिया कैसी होनी चाहिए। भारत द्वारा 2026 में आयोजित होने वाला AI Impact Summit अब वैश्विक एजेंडा-सेटिंग आयोजन बन गया है। यह वही स्थान है जहाँ अमेरिका की जगह अब भारत नई दिशा तय कर रहा है।

बहरहाल, दक्षिण अफ्रीका में हुआ G20 शिखर सम्मेलन एक असहज वास्तविकता लेकर आया, अमेरिका का नेतृत्व डगमगा रहा है। परंतु इसके साथ-साथ इसने एक नई आशा भी जगाई कि भारत विश्व मंच पर एक स्थिर, विश्वसनीय, संतुलित और दूरदर्शी शक्ति के रूप में उभर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ने साबित कर दिया कि भारत अब केवल वैश्विक राजनीति में सहभागी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक शक्ति है। अमेरिका की अनुपस्थिति ने जो खालीपन छोड़ा, भारत ने उसी खालीपन को नेतृत्व से भर दिया। आज दुनिया भारत को सुनती भी है, भारत के साथ चलती भी है और भारत पर विश्वास भी करती है। यह केवल एक शिखर सम्मेलन की कहानी नहीं, यह 21वीं सदी में भारत के उदय की कहानी है।

यह निजी विचार है।

क्रिप्टो करेंसी का चलन, वर्तमान मुद्राओं के चलन को भविष्य में खतरा।

क्रिप्टोकरेंसी, यानी आभासी मुद्रा, आज विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य में एक अभूतपूर्व नवाचार के रूप में उभरी है, और इसके भौतिक अस्तित्व पर सवाल उठाना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।वर्तमान युग तकनीकी और नवाचार का युग है, और डिजिटलाइजेशन की इस लहर में क्रिप्टोकरेंसी ने आर्थिक क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाई है, जहाँ यह मुद्रा न तो हाथों में महसूस की जा सकती है और न ही जेब-पर्स में रखी जा सकती है क्योंकि इसका कोई मुद्रित या हार्ड-कॉपी रूप नहीं है, यह पूरी तरह डिजिटल है। यह विकेंद्रीकृत मुद्रा है, जिसे किसी एक संस्था या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता और इसका संचालन कंप्यूटर एल्गोरिदम पर आधारित है; केवल कंप्यूटर या डिजिटल नेटवर्क में गिना, ट्रांसफर या भुगतान किया जा सकता है, और यह पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के बजाय पियर-टू-पियर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में काम करती है। क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यह गोपनीयता को बेहतर बनाती है । लेन-देन छद्म नामों और पहचान के साथ हो सकते हैं, जिससे निजता सुनिश्चित होती है, जो कुछ संवेदनशील व्यक्तियों को बहुत उपयुक्त लगती है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन-देनों में थर्ड-पार्टी सर्टिफायर्स की ज़रूरत होती नहीं, इसलिए समय और धन की बड़ी बचत होती है, और बैंकिंग दस्तावेज़ों की गुंजाइशदारी भी नहीं होती। पारंपरिक बैंकिंग पर सरकार का नियंत्रण अधिक होता है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी उस नियंत्रण के दायरे के बाहर होती है, जिससे यह भरोसेमंद और सुरक्षित विकल्प बन जाती है; सरकार बैंक खाते को जप्त कर सकती है, लेकिन क्रिप्टो को उसी तरह नहीं, और यह नीतिगत संकट जैसे नोटबंदी या मुद्रा अवमूल्यन का प्रत्यक्ष शिकार नहीं होती। निवेश के दृष्टिकोण से, क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाने वालों के लिए यह आकर्षक है, क्योंकि इसकी कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, जिससे जोखिम भले हो, लेकिन संभावित लाभ अधिक है। वहीं, सीमाओं से परे त्वरित और सस्ती ट्रांसफर क्षमताओं के कारण यह एक वैश्विक आर्थिक पुल का काम करती है।

इतिहास देखें तो सबसे पहली क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन 2009 में सतोषी नाकामोतो के नाम से जानी जाने वाली इकाई ने बनाई थी, और आज 1500 से अधिक क्रिप्टोकरेंसियाँ बाजार में उपलब्ध हैं। हालाँकि, बिटकॉइन अबितियों में सबसे प्रतिष्ठित है; आपको बताया गया कि ÷हर बिटकॉइन का मूल्य ?500 है÷ भले ही यह आकड़ा कालांतर में बदल सकता हो, लेकिन यह दिखाता है कि डिजिटल मुद्रा वास्तविक और उच्च मूल्यवान संपत्ति बन चुकी है, और कुछ लोग इसे ÷डिजिटल गोल्ड÷ भी कहने लगे हैं।

वैश्विक स्तर पर, क्रिप्टोकरेंसी ने अपनी पैठ बना ली है। Chainalysis की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत, पाकिस्तान और वियतनाम जैसी एशियाई देश पूरी तरह से रिटेल क्रिप्टो उपयोग के हब बन चुके हैं। कई देशों में कानूनी रूप से क्रिप्टो की स्वीकृति है, लेकिन बहुत विविधता भी है, अटलांटिक काउंसिल के ट्रैकर के मुताबिक, 75 देशों में से लगभग 45 देशों में क्रिप्टो को पूरी तरह कानूनी माना गया है, 20 में आंशिक प्रतिबंध है, और 10 में व्यापक प्रतिबंध। कुछ राष्ट्र जैसे यूएई, स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर अपने स्पष्ट लाइसेंसिंग ढांचों और नियामक अनुकूलता के कारण ÷क्रिप्टो-फ्रेंडली÷ बन गए हैं। वहीं, केवल कुछ ही देश ऐसे हैं जहां क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है और उस सूची में लंबे समय तक एल साल्वाडोर अग्रणी रहा है पर यह सफलता हमेशा सहज नहीं रही है। क्रिप्टोकरेंसी के कानूनी, वित्तीय और सुरक्षा संदर्भ में गहरी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले, मर्यादा और नियंत्रण का प्रश्न है: कुछ देश पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुके हैं उदाहरण के लिए चीन ने क्रिप्टो लेन-देनों को अवैध घोषित कर दिया है। दूसरी ओर, ऐसे देश हैं जो प्रयोगात्मक या सैंडबॉक्स अनुक्रमण बना रहे हैं ताकि नवाचार और सुरक्षा संतुलन बन सके।

भारतीय संदर्भ में, आपकी चिंता बिल्कुल यथार्थ है: भारत में क्रिप्टोकरेंसी की विधि-सम्मत स्वीकार्यता अभी स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं है। हालाँकि ÷पूर्ण प्रतिबंध÷ के पुराने दावों के बजाय वर्तमान में एक नियंत्रित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश है। हाल के सरकारी दस्तावेज़ों के अनुसार, सरकार क्रिप्टो को पूरी तरह बंद करने की बजाय सीमित निगरानी और पंजीकरण की राह चुन रही है, क्योंकि यदि इसे वित्तीय प्रणाली में शामिल कर लिया जाए तो संभावित प्रणालीगत जोखिम बढ़ सकते हैं। भारत में टैक्स नियम भी पहले ही लागू किए जा चुके हैं, और क्रिप्टो लेन-देन में (धन शोधन विरोधी) और पता सत्यापन जैसे उपायों पर जोर दिया गया है। **यह निजी विचार है।**

भारत के उच्च शिक्षण संस्थान छात्र कल्याण के लिए हुए एकजुट

दूसरा राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन 22-23 नवंबर 2025 को आईआईटी बॉम्बे में हुआ आयोजित

पीआईबी

किशोर और युवा भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की रीढ़ हैं, फिर भी उनकी सहनशक्ति को अकादमिक दबावों, सामाजिक अलगाव और डिजिटल प्रभावों से लगातार चुनौती मिल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2021, और उसके बाद के यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों ने सामूहिक रूप से परामर्श सेवाओं, समावेशी परिसरों और जवाबदेही तंत्रों की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

मानसिक कल्याण न केवल एक सामाजिक आवश्यकता है, बल्कि एक आर्थिक आवश्यकता भी है, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023ङ्क24 और 2024ङ्क25 में रेखांकित किया गया है, जो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादकता को बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ छात्र आबादी आवश्यक है।

दूसरा राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन

दूसरा राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन 22-23 नवंबर 2025 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में लगभग 80 उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई), 115 संकाय सदस्य और 139 छात्र एक साथ आए। इस कार्यक्रम ने उच्च शिक्षा प्रणालियों में मानसिक स्वास्थ्य, लचीलापन और कल्याण को स्थापित करने के राष्ट्रीय एजेंडे को आगे बढ़ाया, जिसने

2024 में आईआईटी हैदराबाद में आयोजित पहले सम्मेलन की गति को बढ़ाया।

दो दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत दीक्षांत समारोह हॉल में एक उद्घाटन सत्र के साथ हुई, जिसमें गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन और एक औपचारिक दीप-प्रज्ज्वलन शामिल था। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, डॉ. विनीत जोशी ने अपनी टिप्पणी दी, जिसके बाद आईआईटी बॉम्बे के निदेशक, प्रो. शिरीष केदारे ने उद्घाटन भाषण दिया, और आईआईटी जम्मू के निदेशक, प्रो. मनोज सिंह गौर ने छात्रों के मानसिक कल्याण को संस्थागत बनाने के महत्व पर जोर दिया। एक मुख्य आकर्षण ÷देश भर में कल्याण की उभरती सर्वोत्तम पद्धतियों का संग्रह 2.0÷ का विमोचन था, जो राष्ट्रव्यापी संस्थानों के दोहराने योग्य मॉडलों का दस्तावेज़ीकरण करता है।

पहले दिन में एक कल्याण प्रदर्शनी, संगोष्ठियाँ और पैनल चर्चाएँ शामिल थीं, जिनमें परामर्श प्रणालियों, सहकर्मी मार्गदर्शन नेटवर्क, डिजिटल कल्याण उपकरणों और छात्र कल्याण को बढ़ावा देने में संस्थागत भूमिकाओं पर प्रकाश डाला गया। ÷भारतीय उच्च शिक्षा में कल्याण का भविष्य÷ पर संगोष्ठी में विकसित हो रही संस्थागत भूमिका पर चर्चा की गई, जबकि ÷पनपता मनः अकादमिक विकास से लेकर आजीवन कल्याण तक÷ पर पैनल ने जांच की कि भावनात्मक लचीलापन को अकादमिक और व्यक्तिगत विकास में कैसे एकीकृत किया जा सकता है।

दोपहर के सत्रों में निम्नलिखित शामिल थे:

क ÷कल्याण के लिए नीतिगत ढाँचेः राष्ट्रीय दिशानिर्देशों से लेकर परिसर कार्यान्वयन तक÷

क ÷मनोसामाजिक चिंताओं की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप÷ क ÷सहयोगात्मक मानसिक स्वास्थ्य ढाँचे÷

विशेषज्ञों ने स्थायी प्रभाव बनाने, सहायता प्रणालियों को मजबूत करने और कल्याण को अकादमिक संस्कृति में शामिल करने के लिए सक्रिय संस्थागत तंत्रों, प्रारंभिक सहायता प्रणालियों और अंतर-संस्थागत भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

दूसरे दिन की शुरुआत परिसर वॉकथॉन के साथ हुई, जिसने शारीरिक और मानसिक कल्याण के बीच संबंध पर जोर दिया, जिसके बाद छात्रों और संकाय के लिए अलग-अलग कार्यशालाएँ हुईं, जो जीवन कौशल, सहकर्मी सहायता, परामर्श योग्यता और डिजिटल कल्याण पर केंद्रित थीं। छात्र समूहों ने बाद में प्रस्तुतियों के माध्यम से नवीन कल्याण पहलों का प्रदर्शन किया।

सम्मेलन का समापन सुश्री रीना सोनोवाल कौली, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समापन समारोह के साथ हुआ। अंतिम सिफारिशों और 2025-26 के लिए अंतर-विश्वविद्यालय कार्य योजना की घोषणा की गई, जिससे एचईआई) में समन्वित कल्याण पहलों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ।

दूसरे राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन ने छात्र और संकाय कल्याण के लिए विविध राष्ट्रीय प्रयासों को एक सुसंगत दिशा में एकजुट किया है और उच्च शिक्षण संस्थानों में संकाय के बीच एक व्यावसायिक कल्याण समुदाय की नींव को मजबूत किया है। 2025-26 के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करके, सम्मेलन ने एक लचीला, समावेशी और जवाबदेह अकादमिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो भारत के उच्च शिक्षा सुधारों के मूल में मानसिक स्वास्थ्य को रखता है।

पहले राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन (2024) में प्रमुख निष्कर्ष

9-10 नवंबर 2024 को आईआईटी हैदराबाद में आयोजित पहले राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन में 100 संस्थानों के 350 हितधारक एक साथ आए और कल्याण को एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में स्थापित किया। मुख्य सिफारिशों में पेशेवर परामर्श प्रणालियाँ, छात्र प्रतिनिधित्व, संकाय और कर्मचारियों के कल्याण की पहल, और बाहरी विशेषज्ञों के साथ सहयोग शामिल थे। इन सिफारिशों ने संस्थागत सुधारों का मार्गदर्शन किया है और ये जुलाई 2025 में जारी किए गए सर्वोच्च न्यायालय के 15-सूत्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

ट्राई ने एक वर्ष में 21 लाख से अधिक फर्जी नंबरों और एक लाख संस्थाओं पर कार्रवाई की

ट्राई ने सभी मोबाइल उपयोगकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपने फोन पर कॉल ब्लॉक करने के साथ-साथ ट्राई डीएनडी ऐप पर भी स्पैम और धोखाधड़ी की शिकायत करें

पीआईबी

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एक परामर्श जारी कर नागरिकों से ट्राई डीएनडी ऐप के माध्यम से स्पैम कॉल/एसएमएस की शिकायत करने का आग्रह किया है। परामर्श में कहा गया है कि केवल व्यक्तिगत डिवाइस पर नंबर ब्लॉक करने से स्पैम को स्रोत पर नहीं रोका जा सकता है।

ट्राई ने पिछले एक साल में, नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, स्पैम और धोखाधड़ी वाले संदेश भेजने में शामिल 21 लाख से अधिक मोबाइल नंबरों और लगभग एक लाख संस्थाओं को डिस्कनेक्ट और ब्लैकलिस्ट किया है। यह दर्शाता है कि उपयोगकर्ताओं की सामूहिक शिकायतें देश भर में दूरसंचार दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ट्राई ने यह कार्रवाई आधिकारिक ट्राई डीएनडी ऐप पर नागरिकों की ओर से स्पैम की सूचना मिलने पर की। जब कोई उपयोगकर्ता ट्राई डीएनडी ऐप पर स्पैम कॉल या एसएमएस की सूचना देता है, तो

इससे ट्राई और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मोबाइल नंबरों का पता लगाने, उन्हें सत्यापित करने और स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट करने में मदद मिलती है। इसके विपरीत, फ़ोन पर किसी नंबर को ब्लॉक करने से वह आपके निजी डिवाइस पर छिप जाता है - इससे धोखाधड़ी करने वाले को नए नंबरों का उपयोग करके दूसरों से संपर्क करने से नहीं रोका जा सकता।

नागरिकों को सलाह दी जाती है कि: आधिकारिक ऐप स्टोर से ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करें स्पैम एसएमएस/कॉल को फोन पर ब्लॉक करने के बजाय उसकी शिकायत ट्राई डीएनडी ऐप पर करें, ताकि अपराधियों की पहचान करने और उनके नम्बर को डिस्कनेक्ट करने में मदद मिल सके।

होटल, उद्योग और किसानों की साझेदारी आपसी विकास के लिए महत्वपूर्ण : सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी

पीआईबी

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने आज आतिथ्य उद्योग से किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के साथ प्रत्यक्ष, संरचित और दीर्घकालिक साझेदारी बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सहयोग अपरिहार्य हैं।

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) द्वारा आयोजित एफपीओ-आतिथ्य और किसान लाभ शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्यक्ष एफपीओ-होटल संपर्क एक हर तरह से शक्तिशाली और जीत के मॉडल का निर्माण करेगा - जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, जबकि होटलों को प्रीमियम, बड़े पैमाने पर रसायन मुक्त सामग्री प्राप्त

करने में सुविधा। डॉ. चतुर्वेदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में अब लगभग 40,000 एफपीओ हैं, जिनमें से कई ऐसे उत्पाद पेश करते हैं जो आतिथ्य क्षेत्र की स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ भोजन की बढ़ती माँग के अनुरूप हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसानों को अभी भी, खुदरा कीमतों पर वस्तुएं खरीदना लेकिन थोक मूल्य पर उत्पाद बेचना–एक उलटे मूल्य निर्धारण चक्र का सामना करना पड़ रहा है। एक असंतुलन जिसे होटलों के साथ सीधी खरीद साझेदारी के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री के कृषि-उद्योग सहयोग को मजबूत करने के आह्वान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी साझेदारियां बिचौलियों को कम करेंगी, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करेंगी, किसानों के लाभ को बढ़ाएंगी तथा आतिथ्य क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद में योगदान और रोजगार बढ़ाने में सक्षम बनाएंगी।

उन्होंने कहा कि सरकार जैविक खेती, जीआई-टैग उत्पादों और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, तथा केरल के कुमारकोम मॉडल को टिकाऊ उद्योग-समुदाय एकीकरण के लिए एक मानक के रूप में उद्धृत कर रही है।

शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक, श्री सुमन बिल्ला ने कहा कि भारत को एक तेज़-तर्रार, संरचित किसान-होटल साझेदारी ढाँचे की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा मॉडल सरकार के दृष्टिकोण को गति प्रदान करेगा और साथ ही ग्रामीण आजीविका को उन्नत करेगा और पर्यटन-संचालित मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा।

आत्मनिर्भर भारत : भारत में हैमर स्मार्ट प्रिसिजन गाइडेड एयर-टू-ग्राउंड वेपन के उत्पादन के लिए बीईएल और सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए

पीआईबी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मेक-इन-इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और फ्रांस की सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस (एसईडी) ने भारत में हाईली एजल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज (हैमर) स्मार्ट प्रिसिजन गाइडेड एयर-टू-ग्राउंड हथियार के उत्पादन हेतु एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते (जेवीसीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में सचिव (रक्षा उत्पादन) श्री संजीव कुमार और सफ्रान के सीईओ श्री ओलिवियर एंड्रीज की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बीईएल के सीएमडी श्री मनोज जैन और एसईडी के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री एलेक्जेंडर ज़िग्लर ने संयुक्त रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह

समझौता 11 फरवरी, 2025 को एयरो इंडिया के दौरान बीईएल एवं एसईडी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में व्यक्त इरादों को औपचारिक रूप देता है और भारत में एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) स्थापित करने की दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। प्रस्तावित जेवीसी को 50:50 शेयरधारिता वाली एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में गठित किया जाएगा, जो भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना की परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हैमर प्रणालियों के निर्माण, आपूर्ति एवं रखरखाव का स्थानीयकरण करेगी। स्वदेशीकरण का स्तर चरणबद्ध रूप से बढ़ाते हुए 60 प्रतिशत तक ले जाया जाएगा, जिसके तहत प्रमुख सब-असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल और यांत्रिक पुर्जों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। उत्पादन प्रक्रिया का हस्तांतरण भी क्रमिक रूप से सम्पन्न होगा, जिसमें अंतिम असेंबली, परीक्षण व गुणवत्ता आश्वासन की जिम्मेदारी बीईएल निभाएगा। हैमर एक युद्ध-सिद्ध, अत्यंत सटीक और मॉड्यूलर डिजाइन वाली हथियार प्रणाली है, जो राफेल व हल्के लड़ाकू विमान तेजस सहित कई प्लेटफॉर्मों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह संयुक्त उद्यम अनुबंध (जेवीसीए) भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को सुदृढ़ बनाने की बीईएल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसके माध्यम से स्मार्ट प्रिसिजन गाइडेड एयर-टू-ग्राउंड हथियारों के निर्माण में सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के व्यापक वैश्विक अनुभव का लाभ भारत में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे उन्नत रक्षा तकनीक के स्वदेशीकरण को नई गति मिलेगी।

सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्र प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में शामिल

एजेंसी। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में उत्साहपूर्वक भाग लिया है। छात्रों ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों और कर्मियों की वीरता और बलिदान के सम्मान में कविताएं, पेंटिंग, निबंध, वीडियो आदि प्रस्तुत किए। छात्रों को भारत के महान योद्धाओं, जैसे कलिंग के राजा खारवेल, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं और आदिवासी विद्रोह के अधिनायकों आदि के अदम्य साहस और सैन्य रणनीतियों को जानने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। 2021 में शुरू की गई परियोजना ÷वीर गाथा÷ का उद्देश्य वीरता पुरस्कार विजेताओं की प्रेरक जीवन गाथाओं का प्रसार करना और छात्रों में देशभक्ति की भावना का संचार करना है।

भारत और ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग, CDS चौहान और ओमानी रक्षा सचिव ने की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

पीआईबी

भारत और ओमान के बीच नियमित संयुक्त अभ्यास, उच्च-स्तरीय दौरे और तीनों सेनाओं के बीच परिचालन समन्वय के साथ मजबूत रक्षा संबंध हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस नवीनतम बैठक से कई चल रही परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ओमान सल्तनत के रक्षा मंत्रालय के महासचिव मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल-ज़ाबी के साथ चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा और साझेदारी के नए क्षेत्रों की खोज के लिए एक व्यापक बैठक की। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अनुसार, चर्चाओं ने प्रस्तावित सैन्य लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स पर काम को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सैन्य संबंधों को गहरा करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने

जहाज निर्माण, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) में सहयोग बढ़ाने और सशस्त्र बलों के बीच मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करने पर भी चर्चा की।

बैठक में रक्षा निर्यात की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ भारत और ओमान दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करना चाहते हैं। दोनों पक्षों ने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, सीमा प्रबंधन ढाँचे में सुधार लाने और भारतीय नौसेना के प्लेटफ ार्मों के लिए सुचारू परिचालन सुनिश्चित करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने ओमान के साथ भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के बढ़ते परिचालन सहयोग को समर्थन देने के लिए उड़ान मंजूरी को सरल बनाने पर भी चर्चा की। भारत और ओमान के बीच नियमित संयुक्त अभ्यास, उच्च-स्तरीय दौरे और तीनों सेनाओं के बीच परिचालन समन्वय के साथ मजबूत रक्षा संबंध हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस नवीनतम बैठक से कई चल रही परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। पिछले महीने, भारतीय सेना ने 22 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित तीसरी सेना-से-सेना स्टाफ वार्ता (AAST) के दौरान ओमान की शाही सेना के साथ अपने रक्षा सहयोग को मजबूत किया।

एक्स पर एक पोस्ट में सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय (एडीजी पीआई) ने कहा कि भारतीय सेना ने ओमान की शाही सेना के साथ रक्षा सहयोग मजबूत किया। भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के बीच तीसरी सेना-से-सेना स्टाफवार्ता एएएसटी 22-23 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

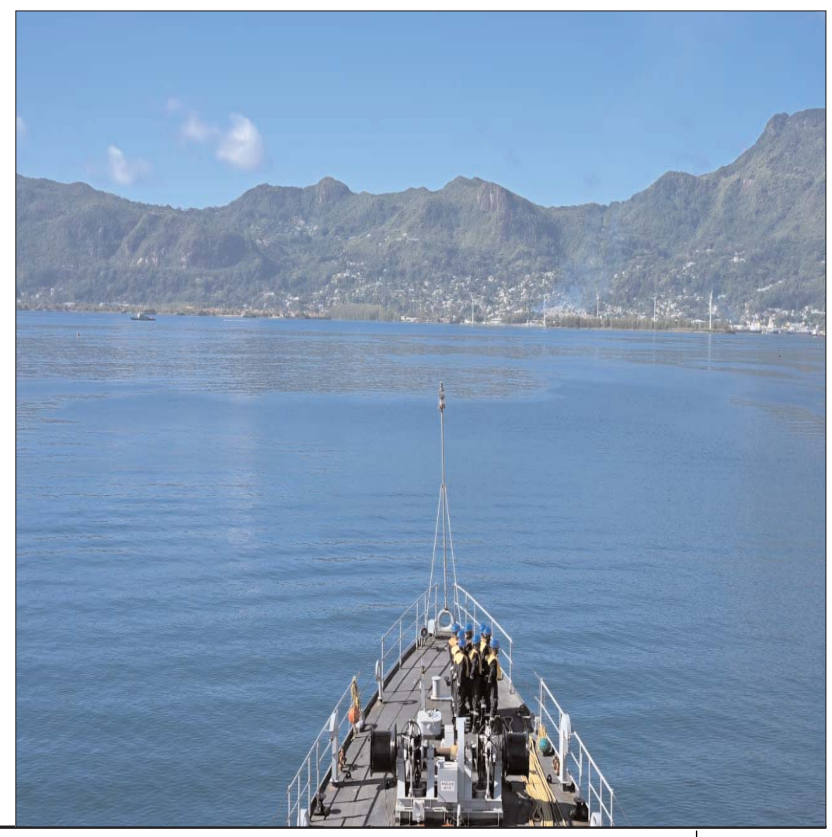

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

हम तो अयोध्या वासी हैं भगवान के स्वाभाविक बाराती ही हैं

स्वधर्मे निधनं श्रेय: पर धर्मो भयाव: - स्वामी मधुसूदनाचार्य जी

जांजगीर चांपा /

श्री शिवरीनारायण मठ महोत्सव में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की कथा का रसपान कराते हुए श्रोताओं से अवधपुरी धाम, उत्तर प्रदेश से पधारे हुए अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज ने कहा कि *भगवान की कथा नित्य नूतन है भले ही आप एक वर्ष में पचास बार सुने लेकिन हर बार नयी अनुभूति होगी* माताओं का बाई अंग फड़कना और पुरुषों का दाहिना अंग फड़कना अत्यंत ही शुभ मानाजाता है। धर्मांतरण के संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि - *भले ही जीवन में कितनी ही विपत्ति क्यों ना आ जाए! अपने धर्म पर ही चलना। किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म नहीं बदलना*। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है *स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावः* अर्थात स्वयं का धर्म ही सर्वश्रेष्ठ होता है, दूसरे का धर्म तो भय और पीड़ा को देने वाला है। सीताराम विवाह महोत्सव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि *हम तो अयोध्या वासी हैं भगवान के स्वाभाविक बाराती हैं, हम बारात में रहेंगे ही* प्रत्येक दिवस की तरह मुख्य यजमान के रूप में राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज मंच पर विराजित थे।

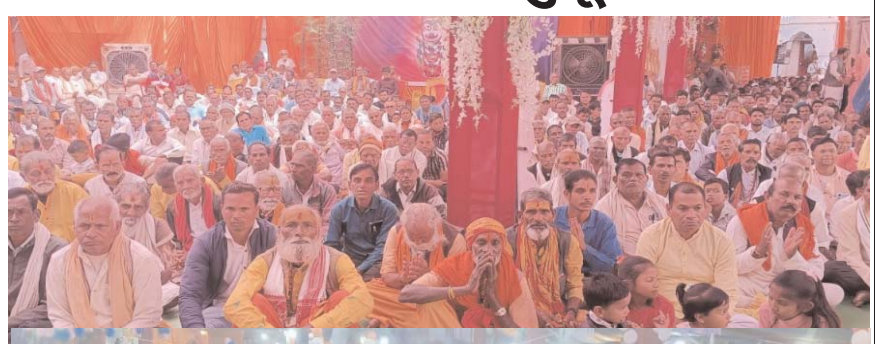

श्री सीताराम विवाह महोत्सव 25 को

शिवरीनारायण नगर में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में और दूर दराज से आने वाले स्रोताओं के मध्य श्री सीताराम विवाह महोत्सव को लेकर अत्यंत उत्साह का वातावरण बना हुआ है, 25 नवंबर को सुबह 9:00 से 12 बजे तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी। सायंकालीन बेला में शाम 3:30 बजे भगवान के बारातियों का भव्य शोभायात्रा नगर में परंपरागत रूप से निकाली जाएगी। शिवरीनारायण नगर निवासी भगवान के बारातियों के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं।

शिवरीनारायण मठ महोत्सव में श्री दूधाधारी मठ के ट्रस्टी ज्योतिंद्रनाथ ठाकुर, राजेश अग्रवाल, विनोद मंगल अग्रवाल, श्री जैतू साव मठ से अजय तिवारी, महेंद्र अग्रवाल, महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय रायपुर के प्राचार्य देवाशीष मुखर्जी, खैरागढ़ जगन्नाथ मंदिर के महन्त राधा मोहन दास जी महाराज सहित अनेक गणमान्य नागरिक गण सम्मिलित हुए।

टेनीकोइट प्रतियोगिता में यशोदा व अमिता बनीं विजेती

अंतरक्षेत्रीय पॉवर कंपनीज खेल स्पर्धा का आयोजन कोटा में

रायपुर। अंतरक्षेत्रीय पॉवर कंपनीज टेनीकोइट प्रतियोगिता का आयोजन कोटा रेयानटर्फ मैदान में किया गया, जिसमें यशोदा रौतिया एवं अमिता बारा विजेती रहीं। प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीमसिंह कंवर रहे। उन्होंने कहा कि टेनीकोइट चुस्ती-फुर्ती और संतुलन का खेल है। यह हमें शरीरिक रूप से मजबूत बनाता है और हमारी कर्तव्य स्थल पर हमारी दक्षता वृद्धि में सहायता करता है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज क्रीड़ा एवं कला परिषद रायपुर क्षेत्र ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें कोरबा पूर्व, कोरबा पश्चिम, रायपुर ग्रामीण व रायपुर सेंट्रल क्षेत्र की टीम शामिल हुई। प्रतियोगिता में कई राऊंड के मैच के पश्चात् फाइनल मुकाबला रायपुर सेंट्रल व रायपुर क्षेत्र के बीच हुआ, जिसमें रायपुर सेंट्रल की यशोदा रौतिया व अमिता बारा विजेता रहीं एवं रायपुर क्षेत्र की अलिश मेरी केरकेट्टा व ज्योति कंवर उपविजेती रहीं। प्रबंध निदेशक श्री कंवर ने अखिल भारतीय महिला टेनीकोइट स्पर्धा हेतु चयनित खिलाड़ियों की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्य अभियंता श्री संजीव सिंह, छत्तीसगढ़ टेनीकोइट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री संजय शर्मा व एसोसिएशन की निर्णायक श्रीमती बी जया लक्ष्मी विशेष रूप से उपस्थित थीं। मंच संचालन प्रबंधक (जनसंपर्क) श्री गोविन्द पटेल एवं आभार प्रदर्शन क्रीड़ा सचिव श्री विनय चंद्राकर ने किया।

नहीं रहे धर्मेंद्र पर फैंस दिलों में सदा रहेंगे जिंदा..

हीमेन धर्मेंद्र को दी गई श्रद्धांजलि

संवाददाता। जांजगीर चांपा - आपको बता दे कि बॉलीवुड के स्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है। देश के जानी मानी हस्ती बॉलीवुड के हीमेन धर्मेंद्र नहीं रहे । निधन की सूचना पाकर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने फिल्मी दुनिया के कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत कर रही है ।

नगर के समाजसेवी एवं लायंस क्लब के अध्यक्ष राजेश पालीवाल, पूर्व एल्डरमैन मनोज कालू अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार पवन अग्रवाल , ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है । अभिनेता धर्मेंद्र अपनी अदाकारी की वजह से लोगो के बीच लोकप्रिय है और उनके फैंस का कहना है कि भले ही आज उनका देहांत हो गया है परंतु अपने फैंस के दिल में सदा ही जिंदा रहेंगे।

आइए जानते है धर्मेंद्र जी के बारे में - धर्म सिंह देओल (जन्म 8 दिसम्बर 1935 मृत्यु 24 नवम्बर 2025), जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ थे वो लोकसभा क्षेत्र बीकानेर के सासंद रहे हैं।

[1] धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के ÷ही-मैन÷ के रूप में जाने जाने वाले धर्मेंद्र ने पांच दशकों के करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। 1997 में, उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। वह भारत की 15 वीं लोकसभा के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। 2012 में, उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

सरकार किसानों की हित संवर्धन के लिए कर रही कार्य - गुलाब सिंह चंदेल

डोंगाकोहरौद खरीदी केंद्र में धान खरीदी का हुआ शुभारंभ

जांजगीर चांपा / डोंगाकोहरौद धान खरीदी केंद्र में आज धान खरीदी का विधिवत शुभारंभ पूजा अर्चना कर किया गया । इस अवसर मुख्य अतिथि गुलाब सिंह चंदेल पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष , विशिष्ठ अतिथि संतोष लहरे पूर्व विधान सभा प्रत्याशी , भूपेंद्र सिंह ठाकुर शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक , देवकुमार पाण्डेय जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवादल , रोहणी पटेल प्राधिकृत अधिकारी , सरपंच प्रतिनिधि दुकालु भास्कर , केसला सरपंच घासीराम पटेल , घनश्याम साहु पूर्व अध्यक्ष , उप सरपंच रथराम पटेल , संतोष कौशिक , जनपद सदस्य प्रतिनिधि संजू कौशिक के आतिथ्य में संपन्न हुआ । इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ व केंद्र की भाजपा सरकार लगातार किसानो की हित संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है जिसका परिणाम यह है कि आज गांव गांव के किसान खुशहाल व समृद्ध है तथा किसानो की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीद रहा है । श्री संतोष लहरे ने अपने उद्बोधन में बताया कि किसानो को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए भाजपा सरकार ने केसीसी योजना प्रारंभ किया था जिसके कारण आज किसान खेती कार्य के लिए साहूकारों पर निर्भर नही है और सरकार से केसीसी लोन लेकर समय पर कर्ज मुक्त हो जाते हैं जो किसानों की समृद्धि का प्रतीक है । इससे पूर्व अतिथियों द्वारा भारत माता व महापुरुषों की पूजा अर्चना किया तत्पश्चात उनका स्वागत शाल श्रीफल पुष्पमाला से किया गया वहीं धान खरीदी शुभारंभ के तौल कांटा का पूजा व किसान का माला पहनाकर अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया।

स्वगत करने वालों में संस्था के प्रबंधक युगल किशोर मैत्री , खरीदी प्रभारी जीवन बर्मन , उमेंद्र कांत , नारायण लहरे , विकास सिंह कक्षवाहा सहित ग्रामीणजन मनोज साहु , हुलास राम कश्यप , पंच शनिचराम कश्यप , अरविंद पटेल , मोहन कश्यप , गोपी कौशिक शामिल रहे । कार्यक्रम में प्रमुख किसान सुदर्शन साहु , कृष्णा पटेल , अंगद कश्यप , हलधर कश्यप , रामकुमार कश्यप , कृष्णकुमार पटेल , लक्ष्मी प्रसाद पटेल , पत्रकार राजकुमार श्रीवास सहित बड़ी संख्या में डोंगाकोहरौद केसला के किसान उपस्थित थे ।

जनदर्शन में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे आवेदकों ने सुनाई अपनी समस्याएं

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई के दिए निर्देश

जनदर्शन में आज कुल 88 आवेदन हुए प्राप्त

जांजगीर-चांपा / कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों और मांगों को गंभीरता से सुना। कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। जनदर्शन में आज कुल 88 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन में आज तहसील पामगढ़ के ग्राम मेहंदी निवासी श्री बजरंग पटेल द्वारा व्हीलचेयर प्रदान करने, ग्राम डुडगा निवासी श्री सुखनंदन सूर्यवंशी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने, तहसील अकलतरा ग्राम गढ़ोला निवासी श्री गंगाराम सूर्यवंशी ने भूमि सीमांकन करवाने, ग्राम मुड़पार के निवासी श्री बसंतकुमार भूमि का नामांतरण करवाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन का प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

स्वच्छता ही सेवा: राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह ने किया ग्राम पंचायत लछनपुर, बसंतपुर, मड़वा, मदनपुर एवं नवागांव का निरीक्षण

जांजगीर-चांपा / राज्य सलाहकार (रा.स्व.भा.मि.ग्रा.) एवं संभाग प्रभारी (बिलासपुर) श्रीमती मोनिका सिंह ने जिले मे जनपद पंचायत बलौदा के ग्राम पंचायत लछनपुर, बसंतपुर, मड़वा, मदनपुर (रैनपुर) एवं नवागांव का निरीक्षण किया। राज्य सलाहकार श्रीमती सिंह ने सभी स्वच्छाग्राही से गांव में हो रहे कचरा कलेक्शन के गीले और सूखे कचरे के पृथकीकरण के विषय में विस्तार से चर्चा किया। साथ ही ग्रामीणों द्वारा घर से देने वाले कचरे को अलग अलग करने हेतु आग्रह एवं सभी लोगो को प्रेरित किया। उन्होंने यूज़र चार्जेस एवं प्रोत्साहन राशि के विषय में चर्चा कर स्वच्छाग्राहियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान गांव में निर्मित सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण कर उनके निरंतर उपयोग व रखरखाव के बारे में बताया गया। इस अवसर पर स्वच्छाग्राही के अध्यक्ष, सचिव, समूह की दीदियां व गांव के सरपंच, सचिव, ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री महोबे ने की साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा

धान खरीदी की नोडल अधिकारियों को खरीदी केन्द्रों की नियमित मॉनिटरिंग एवं साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश

जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं फिकल स्लज प्लांट पर फोकस करने के निर्देश

जांजगीर- चांपा/

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि राज्य के समस्त कार्यालयों कार्यरत शासकीय सेवकों की उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली प्रारंभ किया जाना है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी-अधिकारियों की समय पर उपस्थिति एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए यह प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया कि संबंधित विभाग उपकरण की स्थापना, नेटवर्क कनेक्टिविटी तथा आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूर्ण करें। उन्होंने जिला मुख्यालय के सभी कार्यालयों सहित सभी विकासखंड, तहसील, जनपद पंचायत तथा नगर पालिका, नगर पंचायत कार्यालयों में बायोमैट्रिक मशीनें अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने एवं प्रति साप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा। इसके साथ ही उन्होंने खरीदी केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की सुविधा, तुलाई मशीन एवं सुरक्षाको दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को धान तौल, टोकन, भुगतान संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या न हो। कलेक्टर ने राजस्व से जुड़े प्रत्येक प्रकरण की समयबद्ध एवं प्राथमिकता से समीक्षा कर शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि समस्त विभाग, कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि उनका जीएसटी पंजीयन अवश्य पूर्ण हो। बिना जीएसटी पंजीयन के किसी भी प्रकार की खरीद, खर्च अनुमति योग्य नहीं मानी जाएगी।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने पर भी जोर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर कहा है कि बैंकर्स और वेंडरो की बैठक लेकर अस्वीकृत लोन प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करे। जनपद, नगरीय निकायों में शिविर लगाकर अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना की जानकारी देते हुए लाभान्वित किया जाए। कलेक्टर ने साथ ही सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि सभी हितग्राही-मूलक योजनाओं में लाभ प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्तियों का ई केवाईसी नियमित रूप से कराया जाना अनिवार्य है। सभी विभाग अपने स्तर पर अभियान चलाकर लाभार्थियों के ई केवाईसी को अद्यतन रखें। कलेक्टर ने नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था को सक्रिय करने और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य शिविरों में सामान्य जांच, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ, प्राथमिक उपचार, जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। कलेक्टर ने जिले में जल संरक्षण एवं संचय से संबंधित कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा गया है कि ग्राम स्तर से लेकर शहरी क्षेत्रों तक जल संरक्षण को प्राथमिकता में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए, सरकारी भवनों, स्कूलों, पंचायत भवनों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएँ अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर ने फिकल स्लज प्लांट को शीघ्र शुरू करने करने के निर्देश दिए। साथ ही नागरिकों को इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूक करने तथा प्लांट के महत्व और उपयोगिता की जानकारी व्यापक स्तर पर प्रसारित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा गया है कि सभी कार्य समयबद्ध और पारदर्शी रूप से पूर्ण किए जाएं, ताकि जिले में जल प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण, पोषण ट्रैकर, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, ईऑफिस, समय सीमा के लंबित प्रकरणों सहित विभिन्न विषयों पर समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री आर.के. तंबोली, संयुक्त कलेक्टर श्री संदीप सिंह ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती स्निग्धा तिवारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कल बेजाकब्जा हटाने के आश्वासन पर माने किसान

नैला धान उपार्जन केन्द्र से बेजा कब्जा हटाने की मांग को लेकर विधायक कश्यप के नेतृत्व में किसानों ने किया एसडीएम कार्यालय का घेराव...

जांजगीर-चांपा।

नैला धान उपार्जन केन्द्र से बेजा कब्जा हटाने की मांग को लेकर सोमवार की सुबह किसानों ने जांजगीर चांपा विधायक ब्यास कश्यप के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय जांजगीर का घेराव कर दिया। मौके पर आक्रोशित किसानों का कहना था कि धान उपार्जन केन्द्र में बाऊंण्ड्रीवाल और गेट निर्माण के लिए 2023 में ही राशि स्वीकृत हो चुका है, टेण्डर हुए भी साल भर से ज्यादा बीत चुका है, नगर पालिका की ओर से भी तीन बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जा चुका है जिसके बाद भी प्रशासन अतिक्रमण हटाने में रूचि नहीं ले रहे हैं, उन्होंने साफ चेतावनी दी की बिना अतिक्रमण हटाए नैला धान उपार्जन केन्द्र में धान खरीदी ना किया जाए तथा तत्काल अतिमक्रण हटाया जाए। एसडीएम के टीएल बैठक में होने की वजह से तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने कल अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया जिस पर भी किसान नहीं मांगे जिसपर तहसीलदार मरावी ने विधायक ब्यास कश्यप को एसडीएम से फोन पर बात कराया जिसमें एसडीएम ने भी हर हाल में कल सदलबल जाकर नैला धान उपार्जन केन्द्र से अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया जिसके बाद किसान वापस अपने घर लौटे।

जंगल में हाथियों का हमला, पूर्व उपसरपंच की मौत

तीन साथी सुरक्षित बच निकले

सूरजपुर, जिले के रामकोला वन परिक्षेत्र में शनिवार को हाथियों के दल ने एक बार फिर इंसानों पर हमला कर दिया। जड़ी-बूटी इकट्ठा करने और लापता गाय को खोजने गए गांव के पूर्व उपसरपंच की हाथी के हमले में मौत हो गई, जबकि साथ में गए तीन लोग मौके से जान बचाकर निकलने में सफल रहे।

मिली जानकारी के अनुसार, चार लोग दोपहिया वाहन से जंगल पहुंचे थे। वापसी के दौरान उनका आमना-सामना अचानक हाथियों के झुंड से हो गया। इसी दौरान एक हाथी उग्र हो गया और पूर्व उपसरपंच पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बाकी साथी किसी तरह दौड़कर जंगल से बाहर पहुंचे और घटना की सूचना ग्रामीणों और वन विभाग तक पहुंचाई।

खास खबर

रोदे गांव में संयुक्त दल की कार्रवाई- 42 बोरी अवैध धान भंडारण का हुआ खुलासा

कोरबा)। कलेक्टर श्री अजीत वंसत के निर्देशन में नायब तहसीलदार श्री सुमन मानिकपुरी, सहायक खाद्य अधिकारी सरोज उरेती, मंडी सब-इंस्पेक्टर आकाश भारद्वाज एवं दिनेश कुमार के संयुक्त दल द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान मंडी अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। तहसील पोड़ी उपरोड़ा, विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम रोदे में स्थित विकास जायसवाल के दुकान सह गोदाम में 42 बोरी (16.80 क्विंटल) अवैध रूप से संग्रहित धान पाया गया। नियम विरुद्ध रखे गए इस धान पर मंडी अधिनियम के अंतर्गत तत्काल कार्यवाही की गई।

जांच उपरांत बरामद धान को विधिवत कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति विकास जायसवाल की सुपुर्दगी में दिया गया।

कोरबा बंग समाज ने मनाया 'वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का गौरव

कोरबा। बंग समाज कोरबा द्वारा गुरुवार 22 नवंबर को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य सामूहिक गायन समारोह का आयोजन किया गया। यह ऐतिहासिक आयोजन डीडीएम रोड स्थित कावेरी बैंक्वेट हॉल में शाम 7 बजे प्रारंभ हुआ, जिसमें समाज के सदस्यों ने उत्साह और गौरव के साथ राष्ट्रीय गीत को अपनी सुर लहरियों में पिरोया।

वाद्य और स्वर का मनमोहक संगम कोरबा बंग समाज के सदस्यों द्वारा कई दिनों से वाद्ययंत्रों के साथ सामूहिक अभ्यास किया जा रहा था। उसी तैयारी का उत्कृष्ट प्रदर्शन इस कार्यक्रम में देखने को मिला। प्रसिद्ध तबला वादक एवं प्राध्यापक डॉ. कुणाल दासगुप्ता ने तबला पर संगत दी, जबकि हैप्पी पाल ने हारमोनियम पर सुर सजाए। **राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान का अद्भुत दृश्य** कार्यक्रम के दौरान पूरा हॉल राष्ट्रगीत की स्वर लहरियों से गूंज उठा। सुमधुर और लयबद्ध प्रस्तुति ने उपस्थित दर्शकों को भावविभोर कर दिया। यह अवसर न केवल संगीत का उत्सव था, बल्कि राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक एकता और बंग समाज की परंपराओं का भी अद्भुत संगम रहा। **परिवारों की सहभागिता के साथ सफल कार्यक्रम** इस कार्यक्रम में कोरबा बंग समाज के सैकड़ों सदस्य अपने परिवारों सहित उपस्थित रहे। सभी ने सामूहिक रूप से इस ऐतिहासिक पल को मनाया और राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए बूथ लेवल अधिकारी श्रीमती आरती रात्रे सम्मानित

कोरबा । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गणना पत्रक वितरण एवं डिजिटाइजेशन कार्य 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक संपादित किया जा रहा है। इसी क्रम में कोरबा जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 22 – कटघोरा के मतदान केंद्र 77 – कसईं पाली की बूथ लेवल अधिकारी श्रीमती आरती रात्रे को उनकी उत्कृष्ट एवं समयबद्ध कार्यप्रणाली के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत द्वारा सम्मानित किया गया।

70 वन अधिकारियों के साथ टीम ने 6 अपराधी प्रवृत्ति के घर में मारा छापा

खम्हार समेत साल एवं अन्य प्रजाति के ईमारती वनोपज जब्त

कोरबा । मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त बिलासपुर एवं वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कोरबा द्वारा वनमण्डल अंतर्गत वनों की सुरक्षा, वन्यप्राणियों के सुरक्षा, अवैध कटाई, अवैध उत्खनन अवैध शिकार के प्रकरणों को रोकथाम की मुख्य प्राथमिकता दी गई है। मुखबिरों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22.11.2025 को करतला परिक्षेत्र के प.स.वृत्त रामपुर के रामपुर वन परिसर में ग्राम जोगीपाली नवाडीह में 06 अपराधी प्रवृत्ति के घर में उपवनमण्डलाधिकारी दक्षिण कोरबा, वन परिक्षेत्र अधिकारी करतला, वन परिक्षेत्र अधिकारी पसरखेत, वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा, वन परिक्षेत्र अधिकारी बालको, वन परिक्षेत्र अधिकारी कुदमुरा, वन परिक्षेत्र अधिकारी लेमरु एवं वनमण्डल के अन्य परिक्षेत्र में कार्यरत अन्य 70 वन अधिकारी के साथ 06 पृथक पृथक टीम का गठन कर जारी किये गये सर्च वारंट के तहत् धर्मेन्द्र चैहान, उपवनक्षेत्रपाल, नारंगी ईकाई कोरबा, सहनीराम राठिया, उपवनक्षेत्रपाल, वृत्त वन अधिकारी केराकछार, परिक्षेत्र पसरखेत, संजय केशकर, वनपाल, वृत्त वन अधिकारी कुदमुरा, परिक्षेत्र कुदमुरा, कांति कुमार कंवर, उपवनक्षेत्रपाल, वृत्त वन अधिकारी बालको, परिक्षेत्र बालको, पवन सिंह कंवर, वनपाल, वृत्त वन अधिकारी गढ़, परिक्षेत्र लेमरु, जितेन्द्र केशरवानी, वनपाल, वृत्त वन अधिकारी कोरकोमा, परिक्षेत्र कोरबा द्वारा सर्च वारंट की तामिली कर थाना प्रभारी करतला एवं उनके सर्बधित अधिकारीध्कर्मचारी के सक्रिय एवं सकारात्मक सहयोग से नियमानुसार वृहद तलाशी की कार्यवाही 07 घरों में की गई जो कि पूर्णतः शांतिपूर्ण वातावरण में बिना किसी विवाद के सम्पन्न हुई।

तलाशी में वृहद पैमाने पर मनाराम पटेल पिता स्व. लल्लूराम पटेल, साकिन जोगीपाली (नवाडीह), गनपत पटेल पिता स्व. लल्लूराम पटेल, साकिन जोगीपाली (नवाडीह), पण्डेवालाल पटेल पिता स्व. लल्लूराम पटेल, साकिन जोगीपाली (नवाडीह) भोला पटेल पिता स्व. सम्पत पटेल, साकिन जोगीपाली (नवाडीह), अंकुश पटेल पिता स्व. दिलेश्वर पटेल, साकिन जोगीपाली (नवाडीह), गनेश्वर राठिया पिता स्व. भारत राठिया, साकिन जोगीपाली (नवाडीह) के घर एवं बाड़ी से खम्हार, साल एवं अन्य प्रजाति के ईमारती लगभग 173 नग 4.462 घ.मी., लगभग वनोपज को नियमानुसार जप्त किया गया है। जिसका वन विभाग के वाणिज्यिक दर अनुसारर लगभग मुल्य 160000.00 रुपये है।

दिनांक 14.11.2025 को करतला परिक्षेत्र के रामपुर परिसर में इन्ही अपराधी प्रवृत्ति के ग्रामीणों द्वारा 03 नग साल लठठा अवैध परिवहन करते समय वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पूछने पर उनके साथ मारपीट किया गया था। उक्त 3 नग साल लट्ठा को भी तालाशी के दौरान अपराधियों द्वारा जिसे पैरा में छिपाकर रखे थे वन विभाग एवं थाना प्रभारी करतला एवं उनके सबंधित अधिकारीध्कर्मचारी के सक्रिय एवं सकारात्मक सहयोग से नियमानुसार जप्त किया गया है। 03 नग साल लट्ठा परिवहन करते समय उपयोग में लाये गये ट्रेक्टर को मुखबिर, वृत्त वन अधिकारी रामपुर एवं परिसर वन अधिकारी नोनदरहाध्रामपुर के द्वारा शिनाख्ति के आधार पर ट्रेक्टर को नियमानुसार जप्त कर लिया गया है।

चुनाव आयोग ने शुरू किया विशेष गहन पुनरीक्षण

आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं एस आई आर फॉर्म

कोरबा देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (ैचमबपंस प्दजमदेपअम त्मअपेपवद दृ ैस्) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध बनाना है, जिसमें दोहराए गए नामों, मृत मतदाताओं और गलत प्रविष्टियों को हटाया जाएगा। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं, अगर कोई मतदाता ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहा है या दूसरे शहर में रहता है, तो वह यह प्रक्रिया आसानी से ऑनलाइन पूरी कर सकता है। ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले वोटर आईडी से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो मतदाता को थ्वतउ-8 ऑनलाइन भरकर नंबर लिंक करना होगा। चुनाव आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से पूरी हो जाती है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मतदाता को अवजमते.मबप.हवअ.पद पोर्टल पर 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच रजिस्ट्रेशन करना होगा। लॉग इन करने के बाद वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजें विकल्प के माध्यम से मतदाता पिछले ैस् की सूची में अपना या परिवार का नाम भी देख सकता है। इसके बाद पर क्लिक कर राज्य और म्च्ब्ब् नंबर डालकर प्री-फिल्ड फॉर्म देखा जा सकता है। फॉर्म में नाम, पता, उम्र आदि पहले से भरे होते हैं। जानकारी आधार से मेल नहीं खाने पर बीएलओ से संपर्क करना होगा। मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी सत्यापन के बाद उपयोगकर्ता को तीन विकल्प दिए जाएंगेकृनाम पिछले एसआईआर में मौजूद है, परिवार के किसी सदस्य का नाम मौजूद है या किसी का भी नाम मौजूद नहीं है। संबंधित विकल्प चुनकर आगे की जानकारी भरनी होगी। मतदाता चाहें तो सफेद बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। अंत में के जरिए फॉर्म सबमिट किया जा सकेगा। सबमिशन के बाद मतदाता पोर्टल पर अपने एसआईआर फॉर्म की स्थिति भी ट्रैक कर पाएंगे।

तत्काल न्याय की पहल, 13 दिसम्बर को समझौते से समाधान का सूत्र, निपटेंगे हजारों प्रकरण

तैयारी हेतु बैठक आयोजित

कोरबा) छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषानुसार आगामी 13 दिसम्बर-2025 को जिला एवं तालुका स्तर पर चैथी एवं वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसकी तैयारी के संबंध में 18 नवंबर को श्री संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण की बैठक ली गयी उक्त बैठक बाह्य न्यायालय कटघोरा, करतला, पाली के न्यायाधीशगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम बैठक में भाग लिये। उक्त बैठक में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समस्त न्यायाधीशगण से न्यायालयों में राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीष ने अपने उद्बोधन में व्यक्त किया कि उक्त आयोजित लोक अदालत जन सामान्य को त्वरित सुलभ और सस्ता न्याय प्रदान करने की महत्वपूर्ण पहल है। संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर लोक अदालत में अपनी उपस्थिति सुनिष्चित करने का आग्रह किया गया है ताकि विवादों को आपसी समझौते से समयबद्ध समाधान किया जा सके। लोक अदालत का उद्देष्य न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना, लम्बे समय से लंबित प्रकरणों को समाप्त करना और न्याय पालिका पर बोझ घटाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने अधिकतम लाभ हेतु आम जनता से अपील की है कि वे लंबित प्रकरणों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर तेज परदर्षी और सौहार्द्र पूर्ण न्याय का लाभ उठाये।

उन्होनें बताया कि समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, लोक अदालत की प्रक्रिया बिलकुल संक्षिप्त और साधारण है जिसमें दोनो पक्षों की सहमति से प्रकरण का निपटारा किया जाता है दोनो पक्षों की सहमति से प्रकरण का फैसला होने के कारण पक्ष-विपक्ष में वैमनष्यता, मन-मुटाव हमेषा के लिए समाप्त हो जाता है लोग पुनः सामाजिक जीवन जीने लगते हैं।

अमरिया पारा में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, मायके पक्ष ने ससुराल पर प्रताड़ना के आरोप लगाए

कोरबा, मानिकपुर चौकी अंतर्गत अमरिया पारा बस्ती में शनिवार को एक नवविवाहिता द्वारा फांसी लगाकर जान देने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम करते हुए जांच प्रक्रिया शुरू की। मृतिका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगातार प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं, जिससे प्रकरण संवेदनशील हो गया है।

मृतका की पहचान 22 वर्षीय मधु सूर्यवंशी, निवासी खोखरा (जांजगीर-चांपा) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, मधु ने लगभग नौ महीने पहले अमरिया पारा निवासी अरुण कोसले से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से वह मायके नहीं गई थी और पति व ससुरालजनों के साथ ही रह रही थी।

शनिवार लगभग 11 बजे मधु ने घर में लगे लोहे के एंगल पर दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय पति अरुण घर से बाहर था, जबकि सास-ससुर वहीं मौजूद थे। घटना की खबर मिलने पर अरुण तत्काल घर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी।

मानिकपुर चौकी पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए तहसीलदार को बुलाकर पंचनामा, फोटोग्राफी और अन्य औपचारिकताएं पूरी कराईं। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। उधर, घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के परिजन तत्काल कोरबा पहुंच गए।

सार्वजनिक स्थान पर गाली–गलौच व मारने का प्रयास, अपराध दर्ज

शासकीय कार्य में बाधा, व सचिवों में नाराजगी

कोरबा, । शिकायत की जांच के दौरान एक पंच ने सचिव के शासकीय कार्य में न सिर्फ बाधा पहुंचाई बल्कि गाली-गलौच करते हुए अपमानजनक व्यवहार कर मारने के लिए चप्पल उठा दिया। प्रार्थी मुखी सिंह कंवर पिता स्व. माधोसिंह कंवर निवासी ग्राम रुकबहरी बालको, ग्राम पंचायत रजगामार का सचिव है। घटना दिनांक 13 नवम्बर 2025 को दोपहर करीब 12.32 बजे शिकायत जांच के संबंध में ग्राम पंचायत भवन रजगामार कार्यालय में कार्यवाही चल रहा था तभी बेदराम राठिया वार्ड क्रमांक 1 के पंच द्वारा शराब पीकर पंचायत भवन के अंदर आकर सचिव से गाली- गलौच करते हुए चप्पल उठाकर मारने का प्रयास किया गया। मारपीट की धमकी भी दिया। सचिव मुखी सिंह ने बताया कि इस दौरान सरपंच हरीसिंह राठिया, पंच जनपद पंचायत कोरबा की ओर से अशुतोष मिश्रा भी उपस्थित थे। शांति पूर्ण ढंग से जांच कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही थी। उसी बीच 12.32 बजे बेदराम राठिया पंच द्वारा शराब पीकर पंचायत भवन के अन्दर आकर गाली-गलौच करते हुए चप्पल उठाकर मारना चाहता था। वहां उपस्थित पंच एवं अशुतोष मिश्रा द्वारा बीच बचाव करने से वह बाल-बाल बचा। बेदराम राठिया के खिलाफउचित कार्यवाही नहीं किया गया तो भविष्य में कभी भी कर्मचारियों के ऊपर दुर्घटना घट सकता है। फ्लिहाल मुखी सिंह कंवर की रिपोर्ट पर बेदराम राठिया के विरुद्ध एकमात्र धारा 296-बीएनएस(सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाली-गलौच करना) के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। रजगामार पंचायत भवन में शिकायत को लेकर जांच अर्थात शासकीय कार्य हो रहा था और शासकीय कार्य में पंच के द्वारा बाधा पहुंचाते हुए भयाक्रांत किया गया। इस मामले में पुलिस ने सिर्फ अश्लील गाली-गलौज करने का अपराध दर्ज किया है जबकि शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और आदिवासी सचिव पर चप्पल उठाकर अपमानजनक कार्य करने का अपराध दर्ज नहीं किया गया है। इस घटना से जहां सचिव मुखी सिंह आहत है वहीं सचिव संघ ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर निंदनीय करार दिया है। सचिवों का कहना है कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है।

रायगढ़ जिले के 312 खातों में जमा 3.46 करोड़ रुपए की राशि लौटाई गई

0 आपकी पूँजी, आपका अधिकार अभियान से रायगढ़ में बड़ी पहल

0 जिले के 312 लावारिस खातों से 3.46 करोड़ रुपए का हुआ निराकरण

0 कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कहा- जनता की छूटी हुई हर पूँजी वापस दिलाना शासन की प्राथमिकता

रायगढ़, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशन और छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय सशक्तिकरण नीति को गति देते हुए रायगढ़ जिले में आपकी पूँजी, आपका अधिकार अभियान के तहत लावारिस एवं निष्क्रिय खातों के निपटान में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। जिले के 312 खातों में जमा कुल 3.46 करोड़ रुपए का सफलतापूर्वक निराकरण कर राशि उनके वास्तविक हकदारों को लौटाई गई।

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार शुक्रवार को टीआर संस, बिजनेस हब, एक्सिस बैंक के पास, ढिमरापुर रोड में जिला स्तरीय विशेष शिविर आयोजित किया गया। देशभर के 95 जिलों में आज एक साथ इस अभियान के शिविर हुए। रायगढ़ जिले के शिविर में महत्वपूर्ण रूप से आपकी पूँजी, आपका अधिकार पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। शिविर में रिजर्व बैंक ऑफइंडिया की रीजनल डायरेक्टर श्रीमती रीनी अजीत ने उपस्थित नागरिकों को अभियान के उद्देश्य समझाते हुए बताया कि बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों को शीघ्र, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उनके असल वैध धारकों तक पहुँचाना सरकार और आरबीआई की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए उद्गम पोर्टल को आधुनिक और सरल बनाया गया है, जिसके माध्यम से एक ही क्लिक में 30 बैंकों के अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट देखे जा सकते हैं। आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक दीपेश तिवारी ने पोर्टल के उपयोग की विस्तृत प्रक्रिया बताते हुए कहा कि निष्क्रिय खातों को दावा आवेदन और केवाईसी दस्तावेज जमा कर आसानी से पुनः सक्रिय किया जा सकता है।

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशन में जिलेभर में जारी विशेष अभियान

रायगढ़ जिले में अब तक 79,562 ऐसे बैंक खाते चिन्हित किए गए हैं जिन पर वर्षों से कोई दावा नहीं किया गया है। इन खातों में कुल 37.14 करोड़ रुपए की राशि जमा है। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों और कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और बैंक संयुक्त रूप से सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 3.46 करोड़ रुपये की अदावाकृत राशि का निपटान संभव हो सका है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिकतम 3.11 करोड़ रुपये की राशि का निपटान किया गया, जिससे बड़ी संख्या में नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला। कई परिवार इस राशि का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यकताओं के लिए कर सकेंगे। कलेक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि जनता की छूटी हुई हर पूँजी वापस दिलाना शासन की प्राथमिकता में शामिल है।

शिविर में मिला त्वरित समाधान प्रमाण-पत्र भी वितरित - विशेष शिविर में 250 से अधिक नागरिक पहुंचे। जिन खाता धारकों के दस्तावेज पूर्ण थे, उनके दावे का तत्काल निपटान करते हुए उन्हें प्रमाणपत्र भी सौंपे गए। आधार-पैन से सत्यापन, दावा फॉर्म भरना और निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने की पूरी प्रक्रिया शिविर स्थल पर ही पूर्ण कराई गई। अभियान के तहत जिले के सभी 7 विकासखंडों में शिविर का आयोजन किया जा चुका है। दो विशेष शिविर कलेक्ट्रेट कार्यालय में शासकीय खातों के पुनः सक्रियकरण के लिए किया गया है एवं चार जागरूकता शिविर लगाया जा चुका है। शिविर में अग्रणी बैंक प्रबंधक कमल किशोर सिंह ने यह जानकारी दी। शिविर में श्रीमती रीनी अजीत रीजनल डायरेक्टर, आरबीआई, दीपेश तिवारी, सहायक महाप्रबंधक, आरबीआई, बी.आर. रामकृष्ण नाइक, जोनल हेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धर्मेंद्र रावत, रीजनल मैनेजर, एसबीआई, प्रवीण कुमार, रीजनल मैनेजर, बैंक ऑफबड़ौदा, प्रवीण केतकी, रीजनल मैनेजर, सीजी ग्रामीण बैंक, कमल किशोर सिंह, अग्रणी बैंक प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं अधिकारी उपस्थित थे।

36.74 करोड़ की जल प्रदाय योजना विस्तार से कोरबा में जल आपूर्ति तंत्र होगा सुदृढ़

कोरबा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन के मार्गदर्शन में जिले में पेयजल सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिल रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला खनिज संस्थान न्यास के अध्यक्ष अजीत बसंत ने नगर निगम कोरबा क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए 36.74 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

जल प्रदाय व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा

इस स्वीकृति के बाद शहर में जल आपूर्ति तंत्र के उन्नयन, नई पाइपलाइन बिछाने, जल स्रोतों के विकास तथा आधुनिक तकनीक आधारित वितरण प्रणाली के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे नगर निगम क्षेत्र के हजारों परिवारों को सुरक्षित एवं नियमित पेयजल उपलब्ध होगा। जल प्रदाय योजना विस्तार के अंतर्गत कोरबा में 20 एमएलडी क्षमता वाले जल उपचार संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही 30 बीएचपी के क्लीयर वॉटर पंप मशीनरी के 03 सेट, क्लीयर वॉटर पम्पिंग मेन पाइपलाइन (300-200 मिमी व्यास, 4680 मीटर), क्लीयर वॉटर ग्रैविटी मेन पाइपलाइन (500-200 मिमी व्यास, 10,470 मीटर) एवं 03 उच्च जलागार रुगमरा दृ (1080 केएल) इमलीडूग्गू (1260 केएल) व दादर (2250 केएल) का निर्माण कार्य किया जाएगा।

योजना पूर्ण होने पर कोरबा नगरीय क्षेत्र के मोतीसागर पारा, ईमलीडूग्गू, भिलाई खुर्द, दादर खुर्द, मानिकपुर, खरमोरा, पीएम आवास दादर, बेलगीरी बस्ती, रुमगरा, कोहडिया एवं प्रगतिनगर सहित विभिन्न वार्डों के लगभग 57,740 नागरिक प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

जिला प्रशासन का यह निर्णय कोरबा शहर में पेयजल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे आने वाले समय में जनस्वास्थ्य एवं नगरीय सुविधाओं के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

रायपुर जिले में आज हुई लगभग 74 हजार 337.60 क्विंटल धान खरीदी

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश में जिले के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। जिले में आज धान खरीदी के चौथे दिन 1722 किसानों ने 74 हजार 337.60 क्विंटल धान की खरीदी की गई। इस प्रकार अब तक 3571 किसानों ने 1 लाख 51 हजार 370.40 क्विंटल की खरीदी हुई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में धान खरीदी केन्द्रों में किसानों को आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों में धान बेचने को लेकर उत्साह है।

सुदूर अंचलों में बीएलओ का उत्कृष्ट कार्य : इन्द्रावती नदी पार कर मतदाताओं तक पहुँची प्रशासनिक टीम

बीजापुर, जिला प्रशासन के नेतृत्व में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत बीजापुर के दूरस्थ और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में बीएलओ और प्रशासनिक टीम द्वारा किए जा रहे कार्य ने उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। नदी, पहाड़ और घने जंगलों से घिरे नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में भी प्रशासन मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। भैरमगढ़ ब्लॉक के कुटरु क्षेत्र में बीएलओ और स्थानीय प्रशासनिक टीम ने इन्द्रावती नदी को नाव से पार कर जर्रामरका, हुर्रेगवाली, पुसलंका, चिन्नाटोकामेटा और छोटेबोदली जैसे दुर्गम गांवों में पहुँच बनाई। कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए और कई किलोमीटर पैदल सफर करते हुए टीम ने 300 से अधिक मतदाताओं को गणना पत्रक वितरित किए। बीएलओ ने न सिर्फगणना पत्रक पहुँचाए बल्कि ग्रामीणों को उन्हें सही प्रकार से भरने में भी सहयोग प्रदान किया। इस अभियान में नदी पार करने, घने जंगलों में चलने और लगातार सुरक्षा जोखिमों का सामना करने के बावजूद टीम ने अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। जिला प्रशासन ने इसे अत्यंत सराहनीय कार्य बताया है। अभियान में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सूर्यकांत घरत, सीईओ जनपद पंचायत अभिषेक तंबोली, बीएलओ देवी लाल कंवर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं अन्य सहयोगी सदस्य शामिल रहे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुदूर अंचलों में निवासरत प्रत्येक मतदाता तक पहुंचना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए अनिवार्य है।

अयोध्या धाम के लिए दुर्ग से रवाना हुआ 185 श्रद्धालुओं का जत्था

दुर्ग,। राज्य सरकार की 'श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना' के अंतर्गत आज दुर्ग रेलवे स्टेशन से 185 श्रद्धालुओं का जत्था विशेष ट्रेन द्वारा अयोध्या के लिए रवाना हुआ। फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच यात्रियों को ट्रेन में बैठाया गया। स्पेशल ट्रेन को ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, महापौर अलका बाघमार, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए भोजन, ठहरने और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था की है। रामभक्तों में अयोध्या दर्शन को लेकर उत्साह और उमंग दिखाई दी। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि हम पहली बार रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, सरकार ने जो व्यवस्था की है वह बहुत अच्छी है। इस दौरान श्रद्धालुओं को जनसम्पर्क विभाग की मासिक पत्रिका 'छत्तीसगढ़ जनमन' भी भेंट की गई। इस अवसर पर पर नगर निगम आयुक्त सुमीत अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर हरवंश मिरी, डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव तथा अन्य जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी उपस्थित रहे।

नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में आरोपी को 20 साल की सजा, अदालत ने लगाया अर्थदंड

रायगढ़, । जोबी चौकी क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा न्यायालय ने 8 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान शासन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने बताया कि 14 साल की किशोरी 14 मई 2024 की रात भोजन के बाद अपने कमरे में सोने गई थी, लेकिन अगली सुबह लगभग 6 बजे परिजनों ने उसे घर में नहीं पाया। लड़की के कपड़े भी गायब थे, जिसके बाद पिता ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां खोजबीन की, पर कोई सुराग नहीं मिला। संदेह के आधार पर पिता ने जोबी चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 21 मई 2024 को पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।

जंगल में हाथियों का हमला, पूर्व उपसरपंच की मौत

सूरजपुर, जिले के रामकोला वन परिक्षेत्र में शनिवार को हाथियों के दल ने एक बार फिर इंसानों पर हमला कर दिया। जड़ी-बूटी इकट्ठा करने और लापता गाय को खोजने गए गांव के पूर्व उपसरपंच की हाथी के हमले में मौत हो गई, जबकि साथ में गए तीन लोग मौके से जान बचाकर निकलने में सफल रहे।

मिली जानकारी के अनुसार, चार लोग दोपहिया वाहन से जंगल पहुंचे थे। वापसी के दौरान उनका आमना-सामना अचानक हाथियों के झुंड से हो गया। इसी दौरान एक हाथी उग्र हो गया और पूर्व उपसरपंच पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बाकी साथी किसी तरह दौड़कर जंगल से बाहर पहुंचे और घटना की सूचना ग्रामीणों और वन विभाग तक पहुंचाई।

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विभागीय सूत्रों के अनुसार, क्षेत्र में हाथियों की गतिविधि को देखते हुए ग्रामीणों को जंगल में प्रवेश न करने की हिदायत दी गई थी, इसके बावजूद चारों व्यक्ति थोड़ी देर में लौट आने की बात कहकर जंगल में चले गए थे।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मिसाल

पीएम आवास बनाने के लिए मिले 1 लाख 55 हज़ार रुपए की सहायता

सुकमा, । ग्राम सिलगेर के निवासी कोरसा पोदीया पिता कोरसा डोक्का एक नक्सल प्रभावित एवं सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियाँ, आवागमन की कठिनाइयाँ, सीमित संसाधन तथा विकास कार्यों में निरंतर आने वाली बाधाओं के बीच भी कोरसा पोदीया अपने परिवार के साथ खेती तथा जंगल से प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित परंपरागत आजीविका पर निर्भर रहे हैं। यही उनके परिवार के जीवनयापन का प्रमुख साधन था। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच उन्हें शासन की विकासोन्मुख योजनाओं से जोड़ने हेतु प्रशासन एवं पंचायत के सतत प्रयास किए गए। पात्रता परीक्षण उपरांत उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ङ्क ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत 1.20 लाख रुपये की स्वीकृत राशि प्रदान की गई। साथ ही मनरेगा के माध्यम से 95 दिवस का कुल 23,095 रुपये का मजदूरी भुगतान किया गया, जिसने आवास निर्माण कार्य को गति देने में अत्यधिक सहायक भूमिका निभाई। स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12,000 रुपये की शौचालय निर्माण स्वीकृति भी दी गई।

आरएमटी प्रशिक्षण-आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

नियद नेल्लानार योजना के ग्राम पंचायत सिलगेर मे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विशेष रूप से निर्माण कार्यों में स्थानीय कौशल विकास को बढ़ावा देने की पहल की गई। इस प्रशिक्षण का सबसे सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि कोरसा पोदीया अपने स्वयं के पीएम आवास के निर्माण कार्य में सक्षम रूप से जुड़ पाए। इससे निर्माण की गुणवत्ता बढ़ी, लागत में कमी आई और सबसे महत्वपूर्ण–उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास विकसित हुआ।

सोलर पैनल से मिला ऊर्जा का उजाला

सिलगेर जैसे विद्युत-विहीन और दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में कोरसा पोदीया के परिवार को ऊर्जा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उन्हें सोलर पैनल का लाभ भी प्रदान किया गया। इससे घर में रोशनी, मोबाइल चार्जिंग, बच्चों के लिए रात्रि में अध्ययन और परिवार की सुरक्षा में वृद्धि सुनिश्चित हुं। **कठिन परिस्थितियों के बावजूद पक्के मकान का सपना पूरा** सामग्री की सीमित उपलब्धता, श्रमिकों की कमी और सुरक्षा संबंधित जोखिमों के बीच भी प्रशासन, पंचायत, तकनीकी कर्मियों एवं हितग्राही के प्रयासों से आवास सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया।

कोरसा पोदीया की यह सफलता कहानी सिद्ध करती है कि जब नियद नेल्लानार योजना, आरएमटी प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रशासनिक सहयोग और हितग्राही की मेहनत एकजुट होकर कार्य करते हैं, तो सबसे चुनौतीपूर्ण और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्थायी विकास पूरी तरह संभव है।

जिला सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने कहा कि नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्रों में विकास पहुँचाना प्रशासन के लिए केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि एक संकल्प है। प्रधानमंत्री आवास योजनाङ्कग्रामीण के तहत ग्राम सिलगेर में कोरसा पोदीया जैसे हितग्राही द्वारा कठिन परिस्थितियों में भी अपने आवास का गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूर्ण करना, हमारे प्रयासों की सार्थकता को दर्शाता है। जिला प्रशासन नियद नेल्लानार योजना एवं आरएमटी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण एवं सतत प्रशासनिक सहयोग प्रदान कर हम ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्यरत हैं।

एसआईआर कार्य में बीएलओ पर किसी प्रकार का दबाव नहीं - एसडीएम केशकाल

कोंडागांव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केशकाल ने बताया कि एसआईआर कार्य में संलग्न ग्राम इरागांव के सहायक शिक्षक एवं बीएलओ के रूप में कार्यरत हमारे साथी के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कर रहे थे। उन्हें कार्यालय से किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया था, और न ही उनकी ओर से कार्य संबंधी किसी कठिनाई या असमर्थता का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। वे बिना किसी दबाव के नियमित रूप से कार्य कर रहे थे। एसआईआर कार्य में संलग्न सभी बीएलओ को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने हेतु सुपरवाइजर एवं ऑपरेटर की ड्यूटी लगाई गई है, साथ ही क्लस्टर भी बनाया गया है, जिससे बीएलओ आपस में समन्वय स्थापित कर एक-दूसरे की सहायता कर सकें। विधानसभा क्षेत्र के दो बीएलओ, जिन्होंने लगभग शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कर लिया है, उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। केशकाल विधानसभा क्षेत्र में बिना किसी दबाव के एसआईआर कार्य सुव्यवस्थित योजना के साथ किया जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने यह भी कहा कि यदि किसी बीएलओ या कर्मचारी को किसी प्रकार की समस्या, चाहे पारिवारिक हो या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा हो, तो वे बिना संकोच संपर्क कर सकते हैं।

राज्यभर में एसीबी-ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, शराब घोटाले और डीएमएफ अनियमितताओं से जुड़े 18 ठिकानों पर एक साथ छापे

रायपुर, संवाददाता

रविवार सुबह छत्तीसगढ़ में एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। आबकारी विभाग और डीएमएफ से संबंधित मामलों की जांच के तहत प्रदेशभर में लगभग 18 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। राजधानी रायपुर में रामा ग्रीन कॉलोनी स्थित पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास* के आवास पर टीम ने दस्तावेजों की जांच की। इसी तरह अमलीडीह की ला विस्टा कॉलोनी में कारोबारी हरपाल अरोरा के घर भी सर्च अभियान चलाया गया।

बिलासपुर में शराब कारोबार से जुड़े विवादों में चर्चा में आए अनिल टुटेजा के रिश्तेदार अशोक टुटेजा के ठिकानों की तलाशी ली गई। कोंडागांव में वर्ष 2019-20 के दौरान डीएमएफ सप्लाई से जुड़े कोणार्क जैन के आवास पर कार्रवाई की गई।

जगदलपुर में निरंजन दास के भाई चितरंजन दास के मैत्री संघ स्थित घर की जांच की गई। टीमें विभिन्न स्थानों से फाइलें, लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाल रही हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सभी ठिकाने उन व्यक्तियों से जुड़े

बताए जा रहे हैं जिनपर आर्थिक अनियमितताओं और लाभ पहुंचाने के आरोप हैं।

क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला?

शराब घोटाला वह मामला है जिसमें पूर्व सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर शराब कारोबार से जुड़े राजस्व, टेंडर, वितरण और सप्लाई सिस्टम में गड़बड़ियों के आरोप सामने आए थे। जांच एजेंसियों के अनुसार–

अवैध व अतिरिक्त वसूली के आरोप

शराब बिक्री से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के दावे

सप्लाई में पक्षपात और अनियमित टेंडर प्रक्रिया

कथित रूप से अफ़सरों, कारोबारियों और नेटवर्क की मिलीभगत

इस मामले में कहा गया कि सरकारी प्रणाली के माध्यम से होने वाली शराब बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि को गलत तरीके से मोड़ा गया और इसका लाभ चुनिंदा व्यक्तियों तक पहुंचाया गया। इसी सिलसिले में कई अधिकारियों, कारोबारियों और उनसे जुड़े रिश्तेदारों व सहयोगियों की जांच जारी है।

एसीबी ईओडब्ल्यू की ताजा कार्रवाई को इसी बड़े आर्थिक अनियमितता प्रकरण की आगे बढ़ती कड़ी माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जब्ती और दस्तावेज़ीय जांच के बाद आगे की कानूनी प्रक्रियाएँ तय की जाएंगी।

मैत्री गार्डन निजीकरण की ओर, सेल ने जारी किया विज्ञापन — विरोध तेज

भिलाई, संवाददाता।

भारत-रूस मित्रता के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध भिलाई का मैत्री गार्डन अब निजी हाथों में दिए जाने की प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। सेल (SAIL) प्रबंधन ने गार्डन और उसमें स्थित चिड़ियाघर के संचालन के लिए इच्छुक संस्थाओं से प्रस्ताव मांगते हुए विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन जारी होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मैत्री गार्डन का प्रबंधन अब आउटसोर्स मॉडल या निजी साझेदारी के माध्यम से संचालित किया जा सकता है।

करीब 140 एकड़ क्षेत्र में फैला मैत्री गार्डन वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था और यह लंबे समय से भिलाई स्टील प्लांट से जुड़ी शहर की पहचान का प्रमुख हिस्सा रहा है। गार्डन में मौजूद चिड़ियाघर सफेद बाघों की नर्सरी के रूप में पहचान रखता है और यहां से सफेद बाघ और शेर देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में भेजे जाते रहे हैं। यह स्थल पर्यटन, परिवारिक भ्रमण, बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों और जैव-विविधता संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है।

निजीकरण की प्रक्रिया शुरू होते ही कर्मचारी यूनियनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि निजी प्रबंधन में गार्डन के संचालन का आधार जनहित के बजाय व्यावसायिक लाभ हो सकता है, जिससे प्रवेश शुल्क और उपयोग दरों में बढ़ोतरी होने की आशंका है। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने भी इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को निजी हाथों में सौंपे जाने की यह एक और कड़ी है।

वन्यजीव संरक्षण से जुड़े संगठनों ने भी चिंता जताई है कि निजी संचालन के बाद संवेदनशील प्रजातियों, विशेषकर सफेद बाघों के संरक्षण को प्राथमिकता मिलेगी या नहीं इस पर स्पष्टता जरूरी है। उनका कहना है कि मैत्री गार्डन केवल मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि पर्यावरणीय धरोहर है, इसलिए इसके प्रबंधन में संरक्षण और सार्वजनिक हित सर्वोपरि रहना चाहिए। इस पूरे मामले पर शहर में चर्चा तेज है और नागरिक यह जानने को उत्सुक हैं कि निजीकरण के बाद गार्डन का स्वरूप, संचालन नीति, शुल्क संरचना और पहुंच व्यवस्था किस तरह बदलेगी। फ्लिहाल सेल द्वारा विज्ञापन जारी होने के साथ प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में प्रस्ताव आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने चौपाल लगाकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

रायपुर(संवाददाता)।

उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा आज अपने विधानसभा क्षेत्र कवर्धा के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में जाकर चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा सबसे पहले सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम भैंसबोड़ पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के बीच अपने सहज अंदाज में सभी के साथ जमीन पर बैठकर आमजनों की समस्याओं, मांगों एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना।

इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपने गांव से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं, सड़क, पानी, बिजली, आवास, नाली, शौचालय, सामाजिक भवन, पुलिया एवं अन्य विकास कार्यों से संबंधित मांगें उपमुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रत्येक समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और कई आवेदनों का मौके पर ही निराकरण करते हुए अधिकारियों को शेष मामलों का त्वरित जांच कर समाधान करने के निर्देश दिए।

जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम भैंसबोड़ के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने शीतला मंदिर के पास अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 2.50 लाख रूपए, ग्राम में नाली निर्माण कार्य के लिए 3 लाख रूपए, बजरंगबली मंदिर के पास अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 2.50 लाख रूपए, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 6.50 लाख रूपए, धनगांव चौक में सामुदायिक शौचालय निर्माण, धनगांव चौक में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने की घोषणा की। उन्होंने गाढ़ाघाट में पुलिया निर्माण के लिए स्टीमेट तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन सभी कार्यों की शीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी प्रक्रिया पूरी कराते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाएं तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। भैंसबोड़ में जनसंपर्क कार्यक्रम के पश्चात उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्राम तालपुर, बिरमपुर एवं मचगांव में भी जनसंपर्क कर ग्रामीणों से संवाद किया और समस्याओं को सुना तथा स्थानीय विकास कार्यों की समीक्षा की।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणजनों को संबोधित करते हुए कहा कि जब गांवों का विकास होगा, तभी राज्य और देश सशक्त बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासन हर गांव तक बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि इन चौपालों का उद्देश्य औपचारिकता नहीं बल्कि जनता से सीधा संवाद कर मौके पर ही समस्याओं का समाधान करना है।

जीईएम पोर्टल की कार्यशाला 25 से 27 नवंबर को

जशपुरनगर,(आरएनएस)। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशानुसार भारत सरकार के आरएएमपी योजनांतर्गत जिले में विभागों एवं उद्यमियों को डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से सामाग्रियों की खरीदी एवं उपलब्धता सुनिशिचित करने हेतु 25 से 27 नवंबर 2025 तक जी ई एम पोर्टल की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त जानकारी अनुसार 25 नवंबर को जनपद पंचायत सभाकक्ष पत्थलगांव, 26 नवम्बर को जनपद पंचायत सभाकक्ष कुनकुरी एवं 27 नवंबर 2025 को मंत्रणा सभाकक्ष कलेक्ट्रेट जशपुर में समय प्रातः 11:00 बजे से 1:00 बजे तक आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सर्व उद्यमी यथा निर्माता, अधिकृत विक्रेता, ट्रेडर, एफपी.ओ. समूह, स्वयं सहायता समूह इत्यादि सम्मिलित होकर GeM पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ले सकते है। कार्यक्रम में उद्यमियो का On-Spot पंजीयन भी किया जावेगा। जिस हेतु आवश्यक दस्तावेज पेन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाईल नम्ब, एमएसएमई. उद्यम रजिस्ट्रेशन, बैंक जानकारी, ई-मेल आईडी की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम में सभी उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बना सकते है।

हॉस्पिटल में विद्यार्थियों को हेल्थ केयर के टिप्स

बकावंड, (आरएनएस। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक (सेजेस) विद्यालय बकावंड में अध्ययनरत व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेल्थ केयर के 9वीं से 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकावंड में औधोगिक भ्रमण कराया गया। विद्यार्थियों ने केंद्र में ब्लड प्रेशर लेने, तापमान मापने, इनडोर व ओपीडी पर्ची बनाने आदि कार्यो की जानकारी ली। बीएमओ डॉक्टर हरीश मरकाम स्टाफनर्स, बीपीएम एवं विद्यालय के व्यावसायिक प्रशिक्षक अक्षय कुमार बंजारे एवं व्याख्याता विनायक सिंह, कुलदीप खांडेकर, मुकेश सिंह, पुरुषोत्तम सिंह पैकरा मौजूद थे।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)